धर्मराव शरणप्पा शबादी और अन्य

बनाम

सईदा आरिफा परवीन

(दीवानी अपील संख्या 12512/2025)

07 अक्टूबर 2025

[अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और
एस.वी.एन. भट्टी,* न्यायाधीश]

विचारणीय मुद्दा

क्या आक्षेपित निर्णय दोषपूर्ण और सबूतों के अशुद्धता से **नुकसान उठा रहा** हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता है; क्या उच्च न्यायालय वादी द्वारा अपील/प्रति-अपील के बिना मौखिक उपहार पर निचली अदालत के निष्कर्ष को उलटने में सही है; क्या वादी ने के और ए की बेटी के रूप में अपना दावा सिद्ध किया है; क्या मौखिक उपहार/हिबा के तहत वादी का दावा वैध रूप से साबित होता है, और स्वामित्व 10 एकड़ की विस्तार तक प्राप्त होता है; क्या घोषणात्मक राहत के लिए मुकदमा सीमाबंधन द्वारा वर्जित है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

भारत का संविधान - अनुच्छेद 136 - के तहत साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन - क्या आक्षेपित निर्णय दोषपूर्ण **और साक्ष्य के** अशुद्धता **से नुकसान उठा रहा हैं, जो अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन की प्रत्याभूति देता है:**

अभिनिर्धारित: हालांकि, साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन आम तौर पर इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 136 के तहत नहीं की जाती है, हालांकि, किसी दिए गए मामले में, साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन अनुच्छेद 136 के तहत नहीं की जाती है - सबूतों की गलत मूल्यांकन और आक्षेपित निर्णयों में कुछ असंगत निष्कर्ष, पार्टियों के बीच वास्तविक मुद्दे की मूल्यांकन करने के लिए सबूतों की पुन: मूल्यांकन की प्रत्याभूति - मुख्य रूप से यह परीक्षणने के लिए पुन: मूल्यांकन किया जाता है कि क्या निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को सही ढंग से दर्ज किया है - प्रतिवादी-वादी की आपत्ति कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मौखिक और दस्तावेजी

साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, खारिज कर दिया गया - आक्षेपित निर्णय रद्द कर दिए गए - वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। [अनुच्छेद 14, 15]

अपीलीय न्यायालय - निर्णय को संशोधित करने की शक्ति - प्रतिवादी-वादी द्वारा यह घोषणा के लिए दायर किया गया मुकदमा कि वह वाद संपत्ति - निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया, आंशिक रूप से, मुकदमे की संपत्ति के 18 एकड़ और 21 गुंटा की सीमाबंधन **तक स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की निर्णय प्रदान की, हालांकि, मौखिक उपहार/हिबा पर वादी के मामले पर अविश्वास किया - प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील - उच्च न्यायालय ने मौखिक उपहार को मान्यता दी; निर्णय को संशोधित किया और मौखिक उपहार के माध्यम से उसकी मां द्वारा कथित रूप से उपहार में दी गई 10 एकड़ जमीन और वाद संपत्ति में शेष सीमा में 3/4 हिस्सा शामिल करके वादी के हिस्से को बढ़ाया - क्या उच्च न्यायालय वादी द्वारा अपील/प्रति अपील के बिना मौखिक उपहार पर निचली अदालत के निष्कर्ष को उलटने में सही था:**

अभिनिर्धारित: आक्षेपित निर्णय में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि निर्णय को संशोधित करने के लिए कोई आधार बनाया गया है या नहीं - उच्च न्यायालय ने तथ्य की खोज को बाधित किया, जिससे अपील/प्रति-अपील के बिना मुकदमे में निचली अदालत की निर्णय को संशोधित किया गया - इस प्रकार, इस हद तक, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष मान्य नहीं हैं। [अनुच्छेद 21]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 50, 60, 73 - क्या वादी ने ‘के‘ और 'ए' की बेटी के रूप में अपना दावा स्थापित किया:

अभिनिर्धारित: 1.1 वादी ने 'के' और 'ए' की इकलौती बेटी की वैधता का दावा किया - निचली अदालत ने धारा 73 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, धारा 50 को संदर्भित किया, और, गवाहों की विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और क्षमता का परीक्षण किए बिना, एक अमूर्त तरीके से, माना कि वादी 'के' की बेटी है - यह आगे पाया गया कि इन गवाहों को मात्र सुझाव अभियोजन पक्ष के गवाह 2 और 3 के साक्ष्य को बदनाम नहीं करता है - निचली अदालत यह टिप्पणी करने में विफल रहा कि वादी और गवाह, अपने साक्ष्य के आधार पर, अपने कब्जे में दस्तावेजों को रोक रहे थे, अर्थात्, स्कूल छोड़ने के अभिलेख , राशन कार्ड, आदि - सभी भौतिक पहलुओं पर अभियोजन पक्ष के गवाह 1 से 3 के साक्ष्य में सुधार से प्रशंसा में विकृति स्पष्ट है - जबकि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाह 2 और 3 के साक्ष्य को गवाहों के रूप में स्वीकार किया, जिनके पास 'के' के साथ वादी के ज्ञान का विशेष साधन था। [अनुच्छेद 32, 33]

1.2 मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन करने में मानक परीक्षणों का पालन करने में विफल रहने वाली प्रशंसा, और अमूर्त निष्कर्ष वादी की वैधता की तुलना में 'के' दर्ज किए गए हैं - साक्ष्य में स्वीकार्य प्रासंगिक तथ्यों पर जोर दिया गया है - यह मानते हुए कि साक्ष्य स्वीकार्य है, इसे तीन बिन्दुओ के अनुरूप होना चाहिए - स्थिति या संबंध का प्रमाण हमेशा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से होना आवश्यक नहीं है, लेकिन, जब मौखिक साक्ष्य वह आधार है जिस पर न्यायालय द्वारा राय बनाने की आवश्यकता होती है, तो न्यायालयों को किसी रिश्ते के बारे में आचरण पर एक राय को केवल एक प्रासंगिक तथ्य के रूप में मानने की अनुमति दी जाती है - इसे *'तथ्यात्मक प्रस्ताव'* के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए - वादी द्वारा दावा की गई वैधता को 'के' की बेटी के रूप में स्वीकार करने के अपने दृष्टिकोण में आक्षेपित निर्णय उदार हैं। [अनुच्छेद 33]

मौखिक उपहार/हिबा - उसके तहत दावा - जब साबित नहीं होता है - प्रतिवादी-वादी द्वारा यह घोषणा के लिए दायर किया गया मुकदमा कि वह विवादित संपत्ति की मालिक है - निचली अदालत ने मुकदमे का आदेश दिया, आंशिक रूप से, 18 एकड़ और विवादित संपत्ति के 21 गुंटे की परिमाण तक अभिधान और स्थायी निषेधाज्ञा की निर्णय प्रदान करते हुए, हालांकि, मौखिक उपहार/हिबा पर वादी के मामले पर अविश्वास किया - उच्च न्यायालय ने मौखिक उपहार को मान्यता दी; निर्णय को संशोधित किया और मौखिक उपहार के माध्यम से उसकी मां द्वारा कथित रूप से उपहार में दी गई 10 एकड़ जमीन और वाद संपत्ति में परिमाण के शेष हिस्से में 3/4 हिस्सा शामिल करके उसके हिस्से को बढ़ाया - क्या मौखिक उपहार/हिबा के तहत वादी का दावा वैध रूप से साबित हुआ है, और अभिधान 10 एकड़ की परिमाण तक प्राप्त किया गया है:

अभिनिर्धारित: 1.1 नहीं - कब्जे पर सबूत के अभाव में मौखिक उपहार/हिबा और पूर्व अभियोजन *-8 (उ*सके पक्ष में निष्पादित उपहार ज्ञापन*)* के तहत वादी का दावा विफल हो जाता है*,* और इस मुद्दे का उत्तर प्रतिवादियों के पक्ष में दिया जाता है - आक्षेपित निर्णय तदवचनतः बयानों पर वादी के पक्ष में कब्जा मानते हैं*,* और नीचे की अदालतों ने वर्षों के लंबे अंतराल की मूल्यांकन नहीं करने और विवादित संपत्ति मे वादी की चुप्पी जारी रखने में गंभीर त्रुटि की। [अनुच्छेद 39]

1.2 एक मौखिक उपहार के माध्यम से एक वैध हस्तांतरण का गठन करने के लिए, दाता द्वारा घोषणा की तीन समकालीन शर्तें, प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति, प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जा और समकालीन साक्ष्य के माध्यम से कब्जा स्थापित करना जारी रखने के लिए यह दिखाने के लिए कि हिबा पर कार्रवाई की गई है। [अनुच्छेद 39]

1.3 कब्ज़ा एक वैध मौखिक उपहार का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है - अदालतें किसी पक्ष के कब्जे को उन परिस्थितियों से मानती हैं जो दलील देती हैं और साबित होती हैं - उपहार के तहत कार्य करने का सबूत (उदाहरण के लिए, किराया एकत्र करना, स्वामित्व धारण करना, उत्परिवर्तन) कब्जे के दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है - जबकि मुस्लिम कानून एक लिखित दस्तावेज के बिना मौखिक रूप से उपहार देने की अनुमति देता है, इस तरह के उपहार की वैधता सभी तीन आवश्यक तत्वों के प्रदर्शन पर निर्भर है, विशेष रूप से कब्जे की प्रतिपादन - अदालतें प्राप्तकर्ता के कार्यों के "समकालीन" और "निरंतर" सबूतों की परीक्षण करेंगी और संपत्ति पर नियंत्रण यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कब्जा वास्तव में स्थानांतरित किया गया था - सबूतों की कमी (उदाहरण के लिए, किराया इकट्ठा करने में विफलता, दाता का निरंतर नियंत्रण, उत्परिवर्तन की कमी) यह साबित करने की ओर ले जाएगी कि किसी भी लिखित घोषणा की परवाह किए बिना उपहार कभी पूरा नहीं हुआ था। [अनुच्छेद 38, 39]

1.4 मौजूदा मामले में, एक सुसंगत राजस्व अभिलेख है, पूर्व अभियोजन -2, पूर्व. अभियोजन -3, पूर्व अभियोजन -4, पूर्व अभियोजन -5 और पूर्व प्रतिवाद-9 से प्रतिवाद-43 राजस्व अभिलेख में दिखाया गया है कि प्रतिवादियों के नाम अधिकार अभिलेख (आर ओ आर) और उनके पूर्ववर्तियों को ब्याज में दर्ज किए गए थे, स्वामित्व और कब्जे के स्तम्भ दोनों में - वादी ने मौखिक साक्ष्य रखे, हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी क्षमता में वादी के पक्ष में एक वैध मौखिक उपहार था, अर्थात, एक बेटी के रूप में या अन्यथा - आक्षेपित निर्णय को अलग रखा गया - वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। [अनुच्छेद 39, 49]

परिसीमा अधिनियम, 1963 - अनुच्छेद 58, 59 - संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम - धारा 3 - क्या घोषणात्मक राहत के लिए वाद सीमा द्वारा वर्जित किया गया था:

अभिनिर्धारित: 28.10.2013 को दायर किया गया मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है - मामले में वादी के लिए कार्रवाई का सबसे पहला कारण तब था जब पूर्व अभियोजन -2, दिनांक 06.06.1989, 'के' के कहने पर अस्तित्व में लाया गया था और कार्रवाई का कारण फिर से उत्पन्न हुआ जब पूर्व अभियोजन 3 को अस्तित्व में लाया गया था, स्वर्गीय 'ए बी ' द्वारा वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए - 'ए बी ' को बिक्री के उपकरणों (पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7) को निष्पादित करने के लिए कहा जाता है 02.05.1995 - क्रेताओ के नाम बदल दिए गए हैं, और निरंतर लापरवाही के परिणामस्वरूप पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 द्वारा आवरण किए गए लेनदेन की रचनात्मक सूचना दी जाएगी - वादी के पास 05.01.1989, 29.11.1990,

25.02.1995 और 09.09.2001 को विवादित संपत्ती को अपने नाम पर दाखिल करने का अवसर था - इसके अलावा, प्रतिवादी ने 2013 तक मुकदमा दायर नहीं किया, जो किसी भी मामले में, तीन साल की परिसीमा अवधि से अधिक है - इसलिए, ज्ञान को रचनात्मक सूचना के माध्यम से अभ्यारोपित किया जाता है, और परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का एक सतत कारण था - इसके अलावा, बिक्री के उपकरणों को अलग करने के लिए (पूर्व प्रतिवाद -3 से प्रतिवाद -7), अनुच्छेद 59 के तहत मुआयना को पूरा किया जाना चाहिए - यह स्वयंसिद्ध है कि एक पंजीकृत दस्तावेज वैध रूप से निष्पादित किया गया है - एक पंजीकृत दस्तावेज प्रथम दृष्टया कानून में मान्य है - इस प्रकार, सबूत की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जो अनुमान का खंडन करने के लिए साक्ष्य पेश करता है - इस मामले में, प्रतिवादी उक्त धारणा का खंडन करने में विफल रहा - पूर्व अभियोजन -1 और अभियोजन -2 में उत्परिवर्तन प्रविष्टि, पूर्व. प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 के निष्पादन के साथ मिलकर वाद संपत्ति पर वादी के दावे के लिए संभावित रिष्टि के स्रोत हैं - वादी ने अधिकार अभिलेख के रखरखाव को चुनौती देने में समय पर कार्रवाई नहीं की है,या पंजीकृत बिक्री विलेख, कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर - 23 वर्षों की अवधि के लिए आचरण को एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के आचरण के रूप में मूल्यांकन नहीं की जा सकती है, लेकिन यह उस देखभाल का उपयोग करने में विफलता के बराबर है जो एक उचित रूप से विवेकपूर्ण और सावधान व्यक्ति इन परिस्थितियों में उपयोग करेगा। [अनुच्छेद 44, 46-48]

मुस्लिम विधि- के तहत वैध मौखिक उपहार - की अनिवार्यताएं:

अभिनिर्धारित: मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं - दाता की ओर से देने की इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति; प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति, जो या तो निहित या स्पष्ट हो सकती है; प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की विषयवस्तु को वास्तव में या रचनात्मक रूप से लेना - मुस्लिम कानून के तहत एक उपहार के लिए वैध होने के लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है - एक मौखिक उपहार जो तीन आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है वह पूर्ण और अपरिवर्तनीय है - केवल तथ्य यह है कि एक उपहार को लेखन में कम कर दिया जाता है, इसकी प्रकृति या चरित्र को नहीं बदलता है - उपहार को अभिलेख करने वाला एक लिखित दस्तावेज उपहार का औपचारिक साधन नहीं बन जाता है। [अनुच्छेद 36.1, 36.2]

मुस्लिम विधि - उपहार के तहत - कब्जे का वितरण - कैसे बनाया जाए:

अभिनिर्धारित: कब्जे का वितरण एक वैध उपहार के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है - यह वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है - रचनात्मक कब्जे को दाता द्वारा प्रत्यक्ष कृत्यों

द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जो नियंत्रण को स्थानांतरित करने के लिए एक स्पष्ट इरादा दिखाते हैं - उदाहरण के लिए, दाता राजस्व अभिलेख में प्राप्तकर्ता के नाम के उत्परिवर्तन के लिए आवेदन करता है - कब्जे के वितरण को साबित करने के लिए मौखिक उपहार के तहत कार्य करने का निरंतर प्रमाण महत्वपूर्ण है - प्राप्तकर्ता होना चाहिए इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर "विशेष नियंत्रण" प्रदर्शित करने में सक्षम, जैसे कि किराया एकत्र करके, या दाता द्वारा प्राप्तकर्ता की ओर से उत्परिवर्तन जैसे कार्य करने वाले द्वारा - इसके विपरीत, दाता के किराए का निरंतर संग्रह और प्राप्तकर्ता के स्वामित्व दस्तावेजों या उत्परिवर्तन अभिलेख पर नियंत्रण की कमी इस बात का प्रमाण हो सकती है कि कब्जा स्थानांतरित नहीं किया गया था। [अनुच्छेद 36.4, 36.5]

शब्द और वाक्यांश - "जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार अर्जित होता है" - परिसीमा अधिनियम, 1963 - अनुच्छेद 58। [अनुच्छेद 42]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा .60, 50 - संबंध पर राय, जब प्रासंगिक हो - धारा 50 की रूपरेखा - चर्चा की गई। [अनुच्छेद 26, 26.1, 27] निर्णय विधि का हवाला दिया गया

महेश दत्ताराय तीर्थकर बनाम महाराष्ट्र राज्य **[2009] 3** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक

1122: (2009) 11 सर्वोच्च न्यायालय के मामले **141;** *बनारसी और अन्य बनाम राम फल* **[2003] 2** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **22: (2003) 9** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **606;** *डोलगोबिंद परिचा बनाम निमाई चरण मिश्रा* **[1959]** अनुपूरक **2** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **814: एआईआर 1959** सर्वोच्च न्यायालय **914;** *रामचंद्र रामबक्स बनाम चंपाबाई और अन्य* **[1964] 6** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **814: एआईआर 1965** सर्वोच्च न्यायालय **354;** *फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* **1966** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **ऑनलाइन** सर्वोच्च न्यायालय **55;** *अब्दुल रहीम बनाम एसके अब्दुल जबर* **[2009] 4** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **32: (2009) 6** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **160;** *रशीदा खातून बनाम आशिक अली* **[2014] 11** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **31: (2014) 10** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **459;** *हफीजा बीबी बनाम एसके फरीद* **[2011] 5** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **1155: 2011 5** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **654;** *मंसूर साहेब बनाम सलीमा,* **2024** भारतीय न्याय प्रणाली **1006: [2024] 12** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **923;** *निखिला दिव्यांग मेहता और अन्य बनाम हितेश पी. संघवी और अन्य,* **2025** भारतीय न्याय प्रणाली **485;** *नूरुल होदा बनाम बीबी रायफुन्निसा* **[1995]** अनुपूरक **6** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **110: (1996) 7** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **767;** *प्रेम सिंह और अन्य बनाम बीरबल और अन्य* **[2006]** अनुपूरक **1** उच्च न्यायालय प्रतिवेदक **692: 2006 एआईआर सर्वोच्च न्यायालय 3608 - पर भरोसा किया।**

चंदू लाल अग्रवाल बनाम खलीलार रहमान, **भारतीय विधि रिपोर्ट (1942) 2 कोलकाता 299, 309;** *पोट्टेम सुब्बारायुडु और अन्य बनाम कोठापल्ली गांगुलु नायडू और अन्य, **2000*** सर्वोच्च न्यायालय के मामले **ऑनलाइन आंध्रा प्रदेश 296;** *मुसामुत कमरुन्निसा बीबी बनाम मुसामुत हुसैनी बीबी,* **1880 यूकेपीसी 36 - संदर्भित किया गया।**

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएं

अल-मरघिनानी, बुरहान अल-दीन, अल-हियादाया, कुरान महल, कराची खंड III, पृष्ठ 283; मुल्ला, मुसलमान कानून के सिद्धांत, 20वां संस्करण, अध्याय XI (उपहार) **- संदर्भित किया गया है।**

अधिनियमों की सूची

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882; भारत का संविधान, 1950; साक्ष्य अधिनियम, 1872; परिसीमा अधिनियम, 1963

प्रमुख शब्दों की सूची

मुस्लिम विधि; मौखिक उपहार/हिबा; उत्तराधिकार का मुस्लिम विधि; कब्जे का प्रतिपादन ; रचनात्मक कब्जा; रचनात्मक सूचना; मुकदमे को परिसीमा से रोक दिया गया है; साक्ष्य अधिनियम की धारा 50; भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन; अधिकारों का अभिलेख (आरओआर); उत्परिवर्तन;

कब्जे की धारणा; उत्परिवर्तन की कमी; पंजीकृत बिक्री विलेख; प्रति -अपील / प्रति आपत्ति; राय साक्ष्य; रिश्ते का विशेष ज्ञान; घोषणात्मक विवादित ; स्थायी निषेधाज्ञा; कार्रवाई का निरंतर कारण; असावधानी।

मामले की उत्पत्ति

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 12512/2025

कलबुर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय मे प्रथम अपील संख्या 200204/2019 के दिनांक 06.07.2022 के निर्णय और आदेश से नियमित

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए* अधिवक्ता*:

अधिवक्ता श्री रौफ रहीम, , यश प्रशांत सोनवणे, गोपाल भोसले, सुश्री संगीता भोसले, अली रौफ रहीम, रविन्द्र केशवराव अडसुरे।

प्रतिवादी के लिए* अधिवक्ता*:

श्री. अमीत के. आर देशपांडे, अक्षत श्रीवास्तव, विभोर जैन, श्रीमती पूजा श्रीवास्तव।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

एस.वी.एन. भट्टी, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. दीवानी अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी बेंच, कलबुर्गी में नियमित प्रथम अपील संख्या 200204 /2019 में दिनांक 06.07.2022 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है। दीवानी अपील मूल वाद संख्या 212/2013 में प्रतिवादियों के कहने पर कलबुर्गी में प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश की अदालत में एकमात्र प्रतिवादी वादी है।
3. आक्षेपित निर्णयों में दलीलों, सबूतों और निष्कर्षों के उल्लेख से पहले निम्नलिखित कालक्रम की प्रस्तावना की गई है।

    3.1 खदीजाबी, पति - सैयद अब्दुल बासित ने सर्वेक्षण संख्या 107 में कृषि भूमि के विभाजन और अलग कब्जे के लिए अपने भाई के खिलाफ मूल वाद संख्या 68/1971 दायर किया। (ख) गांव कुसनूर, तालुका और जिला गुलबर्गा (विवादित संपत्ती) में 24 एकड़ और 28 गुंटा क्षेत्र में 207 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। 27.10.1987 को, मूल वाद संख्या 68/1971 का निर्णय किया गया (पूर्व अभियोजन -1), यह घोषणा करते हुए कि विवादित संपत्ति खदीजाबी की है। यह कहा गया है कि 05.12.1988 को, खदीजाबी ने एक मौखिक उपहार/हिबा के तहत, वादी को सर्वेक्षण संख्या 107 में 10 एकड़ जमीन के बारे में बताया। 05.01.1989 को, उपहार ज्ञापन (पूर्व अभियोजन -8) को वादी के पक्ष में खदीजाबी द्वारा निष्पादित किया गया बताया गया है। 06.06.1989 को, खदीजाबी के पक्ष में अधिकारों के अभिलेख ('आरओआर') में अधिकारों के परिवर्तन (पूर्व अभियोजन -2) का पंजीकरण 24 एकड़ और 28 गुंटा की

पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए किया गया था। खदीजाबी की मृत्यु 29.11.1990 (पूर्व अभियोजन -3) को हुई थी। 23.05.1991 को, स्वर्गीय खदीजाबी के पति अब्दुल बासित ने फिर से 24 एकड़ और 28 गुंटा के लिए दाखिल खारिज (पूर्व प्रतिवाद-2) प्राप्त किया। 25.02.1995 को, अब्दुल बास (जैसा कि बिक्री विलेखों में निर्धारित किया गया है) ने पांच बिक्री विलेखों (पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7) के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में 24 एकड़ और 28 गुंटा की क्षेत्र बेची, और पूर्व प्रतिवाद-9 से प्रतिवाद-43 के माध्यम से, विवादित संपत्तिको उनके नाम पर बदल दिया गया है। 09.09.2001 को अब्दुल बासित की मृत्यु हो गई। 28.10.2013 को, मुश्ताक अहमद के साथ सईदा आरिफा परवीन ने मूल वाद संख्या 212/2013 दायर किया, जिसमें यह घोषणा की राहत के लिए प्रार्थना की गई कि वादी विवादित संपत्तिका मालिक है और स्थायी निषेधाज्ञा है। वाद संपत्ति भूमि सर्वेक्षण संख्या 107 है, जो 24-28 महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण है, जो गांव कुसनूर, तालुका और जिला गुलबर्गा में स्थित है। विवादित संपत्ति पूर्व में एक सरकारी सड़क, पश्चिम में सर्वेक्षण संख्या 151, उत्तर में सर्वेक्षण संख्या 106 और दक्षिण में सर्वेक्षण संख्या 119 से घिरी हुई है।

3.2 वादी ने, संशोधन के माध्यम से, एक और घोषणा के लिए प्रार्थना की कि प्रतिवादियों के पक्ष में अब्दुल बास द्वारा दिनांक 25.02.1995 को निष्पादित किए जाने वाले कथित बिक्री विलेख अमान्य हैं और वादी पर बाध्यकारी नहीं हैं (पूर्व प्रतिवाद -3 से पूर्व प्रतिवाद -7)।

4 स्वामित्व की घोषणात्मक राहत और पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 को रद्द करने के समर्थन में वादपत्र में कथन किया गया है कि खदीजाबी की मृत्यु 29.11.1990 को हुई थी, और वादी उसकी इकलौती बेटी और उत्तराधिकारी है। खदीजाबी के पति की भी मृत्यु हो चुकी है, और उन्होंने कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा है। खदीजाबी ने अपने जीवनकाल के दौरान, 05.12.1988 को वादी के पक्ष में वाद संपत्ति में से 10 एकड़ भूमि का मौखिक उपहार/हिबा दिया और कब्जा दिया, जिसे वादी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद, 05.01.1989 को एक उपहार विलेख का ज्ञापन निष्पादित किया गया। मौखिक उपहार और उत्तराधिकार के आधार पर, वादी दावा करता है कि वह विवादित संपत्ति का मालिक है और उसके कब्जे में है। वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 1 पहले वार्षिक वेतन के आधार पर खदीजाबी (मूल मालिक) का कृषि सेवक था। वादी आगे दावा करता है कि प्रतिवादियों को वाद भूमि के स्वामित्व या कब्जे से कोई सरोकार नहीं है। दशहरा अवकाश का लाभ उठाते हुए, वादी ने आरोप लगाया कि 14.10.2013 को, प्रतिवादी वाद भूमि पर आए, वादी को

बलपूर्वक बेदखल करने की कोशिश की, और उसे खाली करने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि उन्होंने जमीन खरीदी है। उन्होंने कृषि कार्यों को रोकने की भी कोशिश की। प्रतिवादियों ने दावा किया कि उन्होंने 25.02.1995 को पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से वाद संपत्ति के कुछ हिस्सों को खरीदा था, जिसमें कथित विक्रेता अब्दुल बास पुत्र सैयद हुसैन साहब था। खरीदे गए हिस्से इस प्रकार हैं: (i) प्रतिवादी संख्या-1: 4 एकड़ 38 गुंटास, (ii) प्रतिवादी संख्या-2: 5 एकड़, (iii) प्रतिवादी संख्या-3: 5 एकड़, (iv) प्रतिवादी संख्या-4: 5 एकड़ और (v) प्रतिवादी संख्या 5: 5 एकड़। वादी का तर्क है कि "अब्दुल बास" पुत्र सैयद हुसैन साहब (बिक्री विलेख का निष्पादक) अस्तित्व में नहीं है, कभी भी मालिक नहीं था, न ही वाद भूमि का मालिक था। बिक्री विलेख खदीजाबी या उनके पति "अब्दुल बासित साहब" द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे। वादी का आरोप है कि प्रतिवादियों ने विवादित संपत्तिपर झूठा दावा करने के लिए ये झूठे बिक्री विलेख बनाए। इसलिए, इन बिक्री विलेखों ने कोई अधिकार, स्वामित्व प्रदान नहीं किया है, और प्रतिवादी विवादित संपत्ति के मालिक नहीं बने हैं। वादी का तर्क है कि राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दर्ज की गई थीं। इसके अलावा, वादी ने कहा कि ये प्रविष्टियां अवैध हैं क्योंकि प्रविष्टियों के दाखिल खारिज के समय वादी और न ही मूल मालिकों को सूचना दिए गए थे। इसलिए, ये प्रविष्टियाँ प्रतिवादियों को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्रदान नहीं करती हैं।

5 प्रतिवादियों ने चारों तरफ मुकदमे का विरोध किया। प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि खदीजाबी विवादित संपत्तिकी मूल मालिक थी, और 29.11.1990 को उसकी मृत्यु हो गई और उसके पति की भी मृत्यु हो गई। हालांकि, वे इस बात से इनकार करते हैं कि वादी खदीजाबी की इकलौती बेटी है, कि खदीजाबी ने कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, कि खदीजाबी ने 05.12.1988 को वादी को 10 एकड़ जमीन का मौखिक उपहार दिया था, या वह कब्जा दिया गया था। प्रतिवादियों के अनुसार, खदीजाबी और उनके पति की मृत्यु हो गई। वे आगे इस बात से इनकार करते हैं कि खदीजाबी ने 05.01.1989 को एक उपहार ज्ञापन निष्पादित किया, या यह कि वादी वाद संपत्ति की कुल क्षेत्र में से 10 एकड़ भूमि का मालिक बन गया। उनका आरोप है कि वादी ने अवैध तरीकों से उनकी संपत्ति हड़पने के लिए एक कहानी रची। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कथित मौखिक उपहार के बारे में 25 वर्षों से नहीं सुना गया है, और कथित उपहार ज्ञापन ने इन सभी वर्षों से दिन का उजाला नहीं देखा है। प्रतिवादी विशेष रूप से इस बात का विरोध करते हैं कि प्रतिवादी संख्या1 खदीजाबी का कृषि सेवक था, या प्रतिवादियों को विवादित संपत्तिके स्वामित्व या कब्जे से कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादी इस बात से इनकार करते हैं कि 14.10.2013 को, उन्होंने वादी को बलपूर्वक बेदखल करने की कोशिश की, या उन्होंने वादी को सूचित किया कि

उन्होंने विभिन्न बिक्री विलेखों के माध्यम से भूमि खरीदी है। प्रतिवादियों का दावा है कि दशहरा अवकाश के दौरान, उन्होंने कृषि कार्यों को रोकने का प्रयास नहीं किया या वादी को खाली करने और कब्जा सौंपने के लिए नहीं कहा। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने कहा कि बिक्री विलेख वादी या उसके माता-पिता द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का दावा है कि वे वास्तविक खरीदार हैं। उन्होंने राजस्व और अन्य अभिलेख का सत्यापन किया और अब्दुल बास @ अब्दुल बासित पुत्र सैयद हुसैन सब के स्वामित्व से संतुष्ट थे क्योंकि यह उनके विक्रेता के नाम पर विधिवत परिवर्तित किया गया था। प्रतिवादियों ने 25.02.1995 को पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से सर्वेक्षण संख्या-107 में भूमि की अपनी व्यक्तिगत खरीद का विवरण दिया, जिसमें प्रत्येक प्रतिवादी के लिए दस्तावेज़ संख्या और रकबा निर्दिष्ट किया गया है। वे दावा करते हैं कि वे बिना किसी हस्तक्षेप के खरीद की तारीख से अपने हिस्से के पूर्ण मालिक के रूप में कब्जे में हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अब्दुल बास @ अब्दुल बासित ने पहले 1981 में प्रतिवादी संख्या-2 के परिवार को घर की संपत्ति बेच दी थी। प्रतिवादियों के नाम उचित प्रक्रिया के बाद इन पंजीकृत बिक्री विलेखों के आधार पर राजस्व अभिलेख में बदल दिए गए थे और किसी भी, विशेष रूप से वादी की आपत्ति के बिना जारी रहे हैं। वे इस बात से इनकार करते हैं कि उक्त बिक्री विलेख प्रतिवादियों को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्रदान नहीं करते थे, या प्रतिवादी मालिक नहीं बने। वे आगे इस बात से इनकार करते हैं कि अधिकार अभिलेख में प्रविष्टियां किए जाने पर वादी, खदीजाबी या उसके पति को सूचना नहीं दिया गया था, या यह कि ऐसी प्रविष्टियां अवैध हैं और प्रतिवादियों को कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्रदान नहीं करती हैं।

6 निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दे और अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए गए थे:

1. क्या वादी यह साबित करता है कि, उसके पास वाद अनुसूची संपत्ति पर अधिकार, हक और स्वामित्व है?

2. क्या वादी आगे यह साबित करता है कि*,* वह इस वाद के दायर करने की तारीख तक वाद अनुसूची संपत्ति पर वैध कब्जे और उपभोग में है*?*

3. क्या वादी आगे यह साबित करता है कि*,* प्रतिवादियों ने वादपत्र में कथित रूप से विवादित अनुसूची संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और उपभोग में हस्तक्षेप किया है*?*

4. क्या आदेश या निर्णय*?*

अतिरिक्त मुद्दे:

1. *क्या वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है?*
2. *क्या वर्तमान रूप में वादी का वाद सुनवाई योग्य है?*

7 वादी ने अपनी ओर से खुद को अभियोजन गवाह 1 और अभियोजन गवाह 2 से 4 के रूप में परीक्षण की और पूर्व अभियोजन -1 से अभियोजन -8 के रूप में चिह्नित किया। दूसरे प्रतिवादी की परीक्षण प्रतिवाद गवाह 1 के रूप में की गई थी, और तीसरे प्रतिवादी की प्रतिवाद गवाह 2 के रूप में परीक्षण की गई थी। पूर्व प्रतिवाद-1 से प्रतिवाद-44 को उनकी ओर से चिह्नित किया गया है।

8 पक्षकारों की संबंधित दलीलों, जहां तक आवश्यक है, पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा दलीलों को लेते समय विज्ञापित किया जाता है। निचली अदालत ने वास्तव में, मुकदमे को आंशिक रूप से घोषित किया, विवादित संपत्ति के 18 एकड़ और 21 गुंटा की परिसीमा तक स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की निर्णय प्रदान की। निचली अदालत ने मौखिक उपहार पर वादी के मामले पर अविश्वास किया, और निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है।

8.1वादी खदीजाबी और सैयद अब्दुल बासित की बेटी थी। यह निष्कर्ष अभियोजन गवाह 2 और अभियोजन गवाह 3 की गवाही पर आधारित थी, जिनके पास पारिवारिक संबंधों के ज्ञान का विशेष साधन था। न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ('साक्ष्य अधिनियम') की धारा 50 को लागू कर के ऐसा किया।

8.2निचली अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 का हवाला देते हुए विवादित हस्ताक्षरों की तुलना की और पाया कि पूर्व अभियोजन -8 (उपहार का ज्ञापन} पर सैयद अब्दुल बासित के हस्ताक्षर बिक्री विलेखों पर उनके हस्ताक्षर से मेल खाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे एक ही व्यक्ति थे।

8.3निचली अदालत ने माना कि मौखिक उपहार पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कब्जे की प्रतिपादन स्थापित नहीं की जा सकी। मुस्लिम कानून के तहत, कब्जे की सुपुर्दगी एक आवश्यक शर्त है। अदालत ने संपत्ति की चौहद्दी में एक विसंगति का भी उल्लेख किया, जैसा कि उपहार ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। इससे उपहार में दिए गए हिस्से की पहचान के बारे में संदेह पैदा हो गया, और यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक वैध उपहार विलेख को वास्तविक कब्जे को सौंपने की आवश्यकता होती है।

8.4 निचली अदालत ने माना कि उत्तराधिकार के मुस्लिम कानून के अनुसार, खदीजाबी की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों के हिस्से को बेटी के 3/4 और पिता के 1/4 हिस्से के रूप में विभाजित किया जाना था।

8.5 बिक्री विलेख केवल 1/4 हिस्से (6 एकड़ और 7 गुंटा) की सीमा तक वैध था। 18 एकड़ और 21 गुंटा के शेष 3/4 हिस्से को शून्य घोषित कर दिया गया था।

9 प्रतिवादियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी पीठ में प्रथम अपील संख्या 200204/2019 दायर किया और आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपील को खारिज करते हुए, यह मानते हुए निर्णय को संशोधित किया कि वादी मौखिक उपहार और पूर्व प्रतिवाद -8 के माध्यम से प्राप्त 10 एकड़ जमीन का पूर्ण मालिक है, और विवादित संपत्ति में शेष क्षेत्र में 3/4 हिस्सा है, यानी 14 एकड़ 28 गुंटा है। परिचयात्मक वृतांत को समाप्त करने के लिए, उच्च न्यायालय ने इन निष्कर्षों को निकाला :

9.1 वादी के खदीजाबी और अब्दुल बासित की बेटी होने के निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा।

9.2 इसने मौखिक उपहार पर निचली अदालत के निष्कर्षों को पलट दिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि सबूतों ने 10 एकड़ जमीन के कब्जे को साबित कर दिया; इस प्रकार, मौखिक उपहार को पूरा करना। यह भी नोट किया गया कि गवाहों अभियोजन गवाह 2 और अभियोजन गवाह 4 की गवाही ने वादी के कब्जे के दावे का समर्थन किया।

9.3 उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए निर्णय को संशोधित किया कि वादी अपनी मां द्वारा उपहार में दी गई 10 एकड़ जमीन का पूर्ण मालिक है, और शेष 14 एकड़ और 28 गुंटा में 3/4 हिस्सा है।

10 इसलिए, प्रतिवादियों के कहने पर यह दीवानी अपील की गई।

11 हमने प्रतिवादियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री रऊफ रहीम और वादी के लिए श्री अमित कुमार देशपांडे को सुना है।

11.1 उच्च न्यायालय और निचली अदालत के निष्कर्षों पर अभ्याक्रमण करने वाले प्रतिवादियों के लिए यह तर्क दिया जाता है कि वे विकृति से भरे हुए हैं और कानून में अनुपलब्ध अनुमानों और धारणाओं से पीड़ित हैं। यह समझाया गया है कि 1990 में खदीजाबी की मृत्यु के बाद, उनके पति, अब्दुल बासित, एकमात्र उत्तराधिकारी बन गए और 23.05.1991 को उनका नाम भूमि अभिलेख में दर्ज

किया गया। 25.02.1995 को, अब्दुल बासित ने पांच पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को भूमि बेच दी। याचिकाकर्ताओं के नाम 1995 से 2022-2023 तक अधिकारों के अभिलेख और फसल खेती पंक्ति पर दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कृषि करों का भुगतान किया है और भूमि के लिए फसल ऋण प्राप्त किया है। प्रतिवादी ने खदीजाबी और अब्दुल बासित की बेटी के रूप में अपने रिश्ते को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया है, और कोई भी प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विध्यालय अभिलेख या विवाह प्रमाण पत्र नहीं था। कभी अपने वंश को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 पर भरोसा किया और तीन "इच्छुक गवाहों" की गवाही को स्वीकार किया। कथित "मौखिक उपहार" और "उपहार ज्ञापन" (हिबानामा) दिनांक 05.01.1989, संदिग्ध और दिखावटी लेनदेन हैं। जबकि खदीजाबी ने वादपत्र में उर्दू में अपने नाम पर हस्ताक्षर किए थे, उपहार विलेख में केवल उनके अंगूठे का निशान है, जिसे किसी ने भी पहचाना नहीं था। इसके अलावा, राजस्व अभिलेख में दस्तावेज़ पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। वादी द्वारा 28.10.2013 को दायर किए गए वाद को परिसीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि यह 1995 के बिक्री विलेख पंजीकृत होने के 18 साल बाद दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने मौखिक उपहार को मान्यता देकर और प्रतिवादी को 10 एकड़ भूमि प्रदान करके अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था, खासकर जब से निचली अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया था और प्रतिवादी ने प्रति-अपील दायर नहीं की थी। जबकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, प्रतिवादी ने 02.01.2023 को उन्हें जबरन बेदखल कर दिया और उनकी जानकारी के बिना भूमि अभिलेख में उसका नाम बदल दिया।

11.2 वादी की ओर से पेश होते हुए, शुरुआत में, यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। दर्ज किए गए निष्कर्ष समवर्ती हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। आक्षेपित निर्णयों का समर्थन करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि खदीजाबी, वाद भूमि की मालिक थी, जिसने वादी को 10 एकड़ का मौखिक उपहार दिया और बाद में 05.01.1989 को उपहार का एक ज्ञापन निष्पादित किया। उसकी मृत्यु के बाद, उसके पति, अब्दुल बासित और वादी को पहली बार में विवादित संपत्ति विरासत में मिली।

अब्दुल बासित की मृत्यु के बाद, वादी एकमात्र मालिक बन गया। यह अभियोजन गवाह -2, एक चचेरे भाई, और अभियोजन गवाह -3, एक बहनोई की गवाही से समर्थित है, जिसे परिवार का गहन ज्ञान था और गवाही दी थी कि वादी खदीजाबी की बेटी है। उपहार ज्ञापन (पूर्व. अभियोजन -8) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करके और गवाहों की गवाही के माध्यम से सिद्ध किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा 14.10.2013 को वादी को बेदखल करने का प्रयास करने के बाद 28.10.2013 को मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमा वैधानिक सीमा अवधि के भीतर है। मौखिक उपहार की आवश्यक शर्तें, जिनमें शामिल हैं - कब्जे की औपचारिक सुपुर्दगी पूरी हुई, जैसा कि एक पड़ोसी अभियोजन पक्ष के गवाह -4 के बयान से पुष्टि की गई थी। इसके अलावा, कथित बिक्री विलेख अब्दुल बास नाम के एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए थे, न कि मृतक अब्दुल बासित द्वारा। यहां तक कि अगर अब्दुल बासित उन्हें मार भी देते हैं, तो वे केवल संपत्ति के 1/4 हिस्से के लिए वैध होंगे।

12 दोनों वकीलों द्वारा कुछ उद्धरणों पर भरोसा किया जाता है, और यदि, विश्लेषण में, वही आवश्यक है तो हम उनका उल्लेख कर सकते हैं।

13 उपरोक्त कथा निम्नलिखित बिंदुओं को विचार के लिए प्रस्तुत करती है।

१. क्या आक्षेपित निर्णय विकृति और सबूतों के गलत पढ़ने से ग्रस्त हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता है?

२. क्या उच्च न्यायालय वादी द्वारा अपील/प्रति-अपील के बिना मौखिक उपहार पर निचली अदालत के निष्कर्ष को उलटने में सही है?

३. क्या वादी ने खदीजाबी और अब्दुल बासित की बेटी के रूप में अपना दावा स्थापित किया?

४. क्या मौखिक उपहार/हिबा के तहत वादी का दावा वैध रूप से साबित होता है, और स्वामित्व 10 एकड़ की सीमा तक प्राप्त होता है?

५. क्या घोषणात्मक राहत के लिए मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है?

बिंदु ।

14 भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की पुन: समीक्षा आमतौर पर नहीं की जाती है। पक्षों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने-अपने तर्कों के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमने आक्षेपित निर्णयों में सबूतों की गलत मूल्यांकन और कुछ असंगत निष्कर्षों पर ध्यान दिया है। पुन: मूल्यांकन मुख्य रूप से यह परीक्षणने के लिए किया जाता है कि क्या विचारण न्यायालय और उच्न्यायालय ने उपलब्ध निष्कर्षों को सही रूप से दर्ज किया है। किसी दिए गए मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन पर रोक नहीं है। इस सिद्धांत को *महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम महाराष्ट्र राज्य*[1] में स्पष्ट किया गया है, जिसने मूल्यांकन पर कानून की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत साक्ष्य और प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

"34. xxxx *यह न्यायालय आम तौर पर अनुच्छेद* 136 *के तहत साक्ष्य की पुन: मूल्यांकन नहीं करता है, लेकिन जब उच्च न्यायालय ने एक दीवानी अपील के मुद्दे में एक तथ्य को पुनर्निर्धारित किया है, और अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में गलती की है, तो उच्च न्यायालय मामले को प्रतिप्रेषण पर लेने के बजाय आगे की देरी को रोकने के लिए सबूतों की फिर से मूल्यांकन कर सकता है। (देखें एनजी दास्ताने बनाम एस. दास्ताने* [(1975) 2 *सर्वोच्च न्यायालय के मामले* 326] *सर्वोच्च न्यायालय के मामले पृष्ठ* 329 *पर।*

35. संविधान के अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय द्वारा तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की शक्ति का प्रयोग करने के प्रश्न पर उपरोक्त संदर्भित निर्णयों की उपरोक्त श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की बारीकी से परीक्षण करने से, इसलिए, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं*:*

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं।
- इस न्यायालय के लिए यह अप्रतिबंधित है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि उच्च न्यायालय ने विकृत या अन्यथा अनुचित कार्य किया है।

---

[1] (2009) 11 एस.सी.सी. 141

- जब पार्टियों द्वारा अपने-अपने मामलों के समर्थन में पेश किए गए साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता से कम हो गए और इस तरह उस पर कार्रवाई करना अत्यधिक असुरक्षित और अनुचित है।
- साक्ष्य और निष्कर्ष की मूल्यांकन प्रक्रिया के कानून की किसी भी त्रुटि से दूषित होती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, अभिलेख की त्रुटियों और साक्ष्यों के गलत पढ़ने के विपरीत पाई जाती है, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य से स्पष्ट रूप से विकृत और असमर्थित होते हैं।
- सबूतों की मूल्यांकन और निष्कर्ष के परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर उल्लंघन होता है या अवैधता प्रकट होती है।
- जहां अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों को विकृत या बिना किसी सबूत या अप्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर दिखाया जाता है या उक्त निष्कर्षों को प्रभावित करने वाली भौतिक अनियमितताएं हैं या जहां अदालत को लगता है कि न्याय विफल हो गया है और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अनावश्यक रूप से अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है।
- जब उच्च न्यायालय ने एक नागरिक अपील में मुद्दे में एक तथ्य को पुनर्निर्धारित किया है, और अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में गलती की है।
- निर्णय उलटने का उचित निर्णय नहीं था।

15 वादी के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को नोट किया गया है, और *महेश दत्ताराय तीर्थकर (उपर्युक्त) में अनुपात को ध्यान में रखते हुए*, हमारा विचार है कि, पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे की मूल्यांकन करने के लिए, आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है।

बिंदु II

16 वादी ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि वह खदीजाबी की इकलौती बेटी और उत्तराधिकारी है। 29.11.1990 को खदीजाबी की मृत्यु हो गई और 09.09.2001 को अब्दुल बासित की मृत्यु हो गई। वादी के अनुसार, जैसा कि उल्लेख किया गया है, खदीजाबी ने अपने जीवनकाल के दौरान, विवादित संपत्ती में 10 एकड़ कृषि भूमि के लिए एक मौखिक उपहार/हिबा दिया और कब्जा दिया, जिसके बारे में कहा गया था कि वादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पूर्व अभियोजन -8 उपहार विलेख का ज्ञापन दिनांक 05.01.1989 को मौखिक उपहार के तथ्य को साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादी मौखिक उपहार के माध्यम से 10 एकड़ के क्षेत्र का दावा करता है। 29.11.1990 को खदीजाबी के निधन के साथ, यह कहा गया है

कि वादी और अब्दुल बासित संपत्ति के हकदार उत्तराधिकारी हैं। चूंकि अब्दुल बासित की मृत्यु 09.09.2001 को हुई थी, इसलिए वादी ने संपूर्ण वाद संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा का दावा किया है।

17 प्रतिवादियों ने 29.11.1990 को खदीजाबी की मृत्यु को स्वीकार किया। वे स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करते हैं कि (ए) वादी खदीजाबी की बेटी है, (बी) खदीजाबी ने विवादित संपत्ती में 10 एकड़ जमीन के लिए एक मौखिक उपहार दिया और (सी) प्रतिवादियों के अनुसार कब्जा उनके पूर्ववर्तियों के हित में था और वर्तमान में पूर्व प्रतिवाद -3 से प्रतिवाद -7 के अनुसार प्रतिवादियों के पास है। यह दावा मौखिक उपहार पर आधारित है जो विवादित संपत्ति को हड़पने के लिए एक मनगढ़ंत संस्करण है।

18 एक मुकदमे का पक्ष न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए केवल निष्कर्षों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कानूनी दायित्व के अधीन नहीं है। आइए परीक्षण करें कि क्या निचली अदालत द्वारा मौखिक उपहार पर निष्कर्ष केवल एक निष्कर्ष है, और क्या उच्च न्यायालय ने अपील या प्रति-अपील के बिना राहत में काफी बदलाव किया है। निचली अदालत ने मौखिक उपहार को खारिज करते हुए, वादी के मामले को 18 एकड़ से अधिक भूमि पर स्वीकार कर लिया और 21 गुंटा (3/4 हिस्सा)। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष को पलटते हुए, वादी की घोषणा के हकदार होने की क्षेत्र को बढ़ाकर राहत को काफी हद तक बदल दिया है। निचली अदालत ने स्थायी निषेधाज्ञा की राहत दी और माना कि खदीजाबी की 18 एकड़ और 21 गुंटा की संपत्ति में 3/4 हिस्से का स्वामित्व स्थापित किया गया था। अपीलीय न्यायालय ने हिबा के माध्यम से उसकी मां द्वारा कथित तौर पर उपहार में दी गई 10 एकड़ जमीन और शेष 14 एकड़ और 28 गुंटा में 3/4 हिस्सा शामिल करके उसके हिस्से को बढ़ाया; इस प्रकार, कुल 24 एकड़ और 28 गुंटा। अब, हम निर्णय को संशोधित करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति का उल्लेख करते हैं।

19 *बनारसी और अन्य बनाम राम फल में*[2], इस न्यायालय ने माना कि:

> *"8. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 और 100 क्रमशः प्रत्येक मूल* निर्णय *या अपील में पारित प्रत्येक* निर्णय *से अपील करने का प्रावधान करती है; किसी भी प्रावधान में उस व्यक्ति की गणना नहीं की गई है जो अपील दायर कर सकता है। हालांकि, यह निर्णयों के एक लंबे कैटिना द्वारा तय किया जाता है कि अपील दायर करने का हकदार होने के लिए व्यक्ति को* निर्णय *से व्यथित होना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति* निर्णय *से पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है, तब तक वह अपील दायर करने का हकदार नहीं है (देखें फूलचंद और अन्य. बनाम गोपाल लाल, [1967] 3* उच्च न्यायालय प्रतिवेदक *153;*

---

[2] (2003) 9 एस.सी.सी. 606

श्रीमती जाटन कंवर गोलचा बनाम मैसर्स गोलचा संपत्ती *(प्रा) लिमिटेड, [1970] 3* सर्वोच्च न्यायालय के मामले *573; श्रीमती गंगा बाई बनाम विजय कुमार और अन्य, [1974] 2* सर्वोच्च न्यायालय के मामले *393।* ***कोई अपील केवल एक निष्कर्ष के खिलाफ नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 और 100 दोनों आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान करती हैं, न कि निर्णय के खिलाफ।***

13. ***इसलिए, हमारी राय है कि वादी-प्रतिवादी द्वारा ली गई*** *प्रति* ***अपील या*** *प्रति आपत्ति* ***के अभाव में प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास*** *निर्णय* ***को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिस तरह से उसने किया है।*** *अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई अपील के दायरे के भीतर, प्रथम अपीलीय न्यायालय या तो अपील की अनुमति दे सकता था और प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर सकता था या* निर्णय *के बाद के भाग को हटा सकता था, जिसने* निर्णय *के संदर्भ में धन जमा करने के लिए प्रतिवादी की विफलता पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए* निर्णय *प्रदान की थी, या* निर्णय *को बनाए रख सकता था क्योंकि यह* निर्णय *को खारिज करके पारित किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जो किया है, वह न केवल निर्णय को उस हद तक रद्द करने के लिए है जिस हद तक वह अपीलकर्ताओं के पक्ष में था, बल्कि बेचने के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक पूर्ण और* मुख *निर्णय भी प्रदान की है, जो अपीलकर्ताओं के पूर्वाग्रह के लिए है और प्रतिवादी के लाभ के लिए है, जिसने न तो अपील दायर की है और न ही कोई प्रति आपत्ति लिया है।*

(***जोर दिया गया***)

20 मौखिक उपहार/हिबा पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का संयोजन आक्षेपित निर्णय के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा बताई गई दुर्बलता की व्याख्या करेगा।

समस्या	**विचारण न्यायालय की तर्कशक्ति**	**उच्च न्यायालय की तर्कशक्ति**
हिबा की वैधता मुस्लिम विधि मे	दिनांक 05.12.1988 के मौखिक उपहार के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया गया, क्योंकि 10 एकड़ की पहचान को लेकर संदेह था, जो कि प्रदर्शनी-अभियोजन-8 में सीमा संबंधी विसंगतियों के कारण उत्पन्न हुआ।	न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटते हुए कहा कि यह निष्कर्ष कि उपहार-पत्र पर अमल नहीं किया गया, स्वीकार्य नहीं है। साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि कब्जा सौंपा गया था और इस प्रकार उपहार पूर्ण हो गया

	परीक्षण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक कब्जा हस्तांतरित नहीं किया गया था।	तथा वादी ने उसका कब्जा प्राप्त किया। सीमा संबंधी विसंगतियों के निष्कर्ष का खंडन करने हेतु उच्च न्यायालय ने इसे कमजोर प्रारूपण और अपर्याप्त प्रतिपरीक्षण का परिणाम माना।
वादगत संपत्ति का कब्जा	परीक्षण न्यायालय ने वादी के कब्जे के मामले को उसकी विरासत में प्राप्त हिस्से तक स्वीकार किया।	वादी का कब्जा उसकी हिस्सेदारी के शेष भाग पर उसकी माता की मृत्यु के बाद भी जारी माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, माता-पुत्री संबंध के कारण उपहार में दी गई भूमि पर कब्जा सौंपे जाने का भी अनुमान लगाया गया।

21. बनारसी (उपर्युक्त) में अनुपात को लागू करके, हम देखते हैं कि आक्षेपित निर्णय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि निर्णय को संशोधित करने के लिए कोई आधार बनाया गया है या नहीं। उच्च न्यायालय ने तथ्य की एक खोज को बाधित कर दिया है, जिसके कारण मूल वाद संख्या 212/2013 में निचली अदालत की निर्णय को अपील/प्रति-अपील के बिना संशोधित किया गया है। इस हद तक, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तर्कसंगत नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए अन्य कारणों की स्वतंत्र रूप से परीक्षण की जाती है, जबकि हिबा और वादी की याचिका पर खदीजाबी की बेटी के रूप में विचार किया जाता है। इस बिंदु पर खोज, जिसे अवैधता के रूप में नोट किया गया है, अन्य मुद्दों पर विचार करने का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है।

बिंदु III

22 वादी खदीजाबी और अब्दुल बासित की इकलौती बेटी का दर्जा देने का दावा करता है। 29.11.1990 को खदीजाबी की मृत्यु हो गई और 09.09.2001 को अब्दुल बासित की मृत्यु हो गई। यह मुकदमा 28.10.2013 को दायर किया गया था, यानी खदीजाबी के निधन के लगभग 23 साल बाद और अब्दुल बासित के निधन के 12 साल बाद। प्रतिवादियों ने वादी द्वारा खदीजाबी और अब्दुल बासित की इकलौती बेटी और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दावा किए गए दर्जे से इनकार कर दिया। प्रतिवादियों का तर्क है कि वादी द्वारा दावा किया गया वंश विशेष रूप से वाद संपत्ति के संबंध में है। निचली अदालत , साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 का हवाला देते हुए और अभियोजन पक्ष के गवाह 2

और 3 के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करते हुए वादी की स्थिति पर निष्कर्ष निकालता है कि वादी खदीजाबी और अब्दुल बासित की बेटी है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से मोटे तौर पर सहमति व्यक्त की है।

23. श्री रऊफ रहीम का तर्क है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 किसी व्यक्ति के बारे में राय साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जिसके पास रिश्ते के मुद्दे पर एक तथ्य पर ज्ञान का विशेष साधन है। धारा 50 की आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाता है, और एक गवाह का मात्र बयान मृतक खदीजाबी के साथ संबंध के दावे का निर्णायक नहीं है। धारा 50 में राय साक्ष्य की अनुमति देने के लिए तीन चरण हैं, और अगली सीमा यह है कि साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहों को विश्वसनीयता, विश्वसनीयता के अनुरूप होना चाहिए और मौखिक साक्ष्य को किसी पक्ष के पक्ष में निर्णय लेने के रूप में मानने के लिए अदालत में विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित निर्णयों ने वादी की ओर से परीक्षण किए गए गवाहों की भरोसे या विश्वसनीयता को तौले या परीक्षण किए बिना, एक अमूर्त तरीके से मौखिक साक्ष्य को पुन: प्रस्तुत किया है। आम तौर पर, सबसे अच्छा सबूत दस्तावेजी साक्ष्य होता है, और वादपत्र में दिखाई गई परिस्थितियाँ बताती हैं कि सबूत स्थिति दस्तावेजी साक्ष्य जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल में प्रवेश और छोड़ने का अभिलेख , मतदाता सूची, राशन कार्ड या किसी भी समकालीन दस्तावेज के माध्यम से हो सकती है जहां मृत माता-पिता ने वादी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि सबसे महत्वपूर्ण संदिग्ध परिस्थिति, जिसे अदालतों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, वह यह है कि खदीजाबी के निधन के ढाई दशक बाद और अब्दुल बासित के निधन की तारीख से बारह साल बाद बेटी के रूप में दर्जा का दावा काफी देर से आ रहा है। निचली अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 का हवाला देते हुए, एक लिखावट विशेषज्ञ की भूमिका निभाई और पूर्व अभियोजन -8, एक विवादित दस्तावेज, और पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 के बीच हस्ताक्षरों की तुलना की। अदालत, असाधारण मामलों में, एक लिखावट विशेषज्ञ की कुर्सी पर बैठती है और एक स्वीकृत हस्ताक्षर के साथ विवाद में हस्ताक्षर की तुलना कर सकती है। मौजूदा मामले में, वादी पूर्व प्रतिवाद-3 को प्रतिवाद-7 में स्वीकार नहीं करता है, और प्रतिवादी पूर्व अभियोजन -8 को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खदीजाबी के साथ वादी के संबंध में आचरण के बारे में सबूतों की झलक के साथ कोई सबूत या अनुमान नहीं है। स्थिति एक महत्वपूर्ण घोषणात्मक राहत है, निष्कर्ष अपने आप में विकृत हैं, और वादी खदीजाबी की बेटी के रूप में अपनी स्थिति साबित करने में विफल रहा।

24. श्री अमित कुमार देशपांडे का तर्क है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 किसी पक्ष की स्थिति या संबंध के प्रमाण में मौखिक साक्ष्य जोड़ने का अवसर प्रदान करती है, जो कि मुद्दे में एक तथ्य है। कानून में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि केवल दस्तावेजी साक्ष्य ही अदालत को किसी पक्ष द्वारा दावा की गई स्थिति पर निर्णय लेने में सक्षम बना सके। अभियोजन पक्ष के गवाह 2 और 3 के साक्ष्य अनुकूल, सुसंगत और इसमें विशेष ज्ञान के साधन हैं; इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाह 2 और 3 के साक्ष्य को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है।

25. तर्क के दो पहलू हैं: (i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के तहत साक्ष्य का दायरा, मूल्यांकन और प्रयोज्यता, और (ii) क्या, स्थापित सिद्धांतों पर, मौखिक साक्ष्य वादी की दावा गई स्थिति को खदीजाबी की बेटी के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।

26. *डोलगोबिंद परिचा बनाम निमाई चरण मिश्रा*[3] तथ्य के मुद्दे पर संबंधों पर राय साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 की रूपरेखा की मूल्यांकन करने के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को *डोलगोबिंद परिचा (उपर्युक्त) से निकाला जा सकता है*:

अ. धारा 50 विशेष रूप से विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति के आचरण द्वारा व्यक्त की गई राय को प्रासंगिक बनाती है।

आ. अनुभाग की प्रयोज्यता के लिए, तीन आवश्यक बातें हैं।

१. सबसे पहले, अदालत को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संबंध के बारे में एक **राय** बनानी होगी।

२. दूसरे, इस संबंध पर राय **आचरण के माध्यम से व्यक्त की जानी चाहिए**।तीसरा, जिस व्यक्ति का आचरण राय व्यक्त करता है, उसके पास इस विषय पर **ज्ञान के विशेष साधन** होने चाहिए, जैसे कि परिवार का सदस्य होना या अन्यथा।

इ.शब्द "राय" को एक आकस्मिक बयान या गपशप के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि "निर्णय या विश्वास" या "दृढ़ विश्वास" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विश्वास व्यक्ति के **आचरण या व्यवहार** के माध्यम से प्रदर्शित और सिद्ध होता है। आचरण एक अवधि का होना चाहिए जिसे केवल रिश्ते के बारे में उस आंतरिक विश्वास के अस्तित्व से समझाया जा सकता है।

---

[3] ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 914

26.1. *चंदू लाल अग्रवाल बनाम खलीलार रहमान*[4] ने यह कहते हुए और स्पष्ट किया कि आचरण रिश्ते का अंतिम प्रमाण नहीं है, बल्कि एक मध्यवर्ती कदम है। यह अदालत को उस व्यक्ति की "राय" का अनुमान लगाने की अनुमति देता है जिसका आचरण साक्ष्य में है। अदालत तब इस राय को मुद्दे में रिश्ते के बारे में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तौलती है। इसलिए, धारा 50 केवल सामान्य प्रतिष्ठा (आचरण के बिना) के साक्ष्य को रिश्ते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं बनाती है। इसके अलावा, यदि आचरण इस तरह की अवधि का है, तो न्यायालय को केवल एक प्रासंगिक साक्ष्य मिलता है, अर्थात् किसी व्यक्ति की राय। यह अभी भी न्यायालय के लिए बना हुआ है कि वह इस तरह के सबूतों को तौले, और प्रश्न में संबंध के बारे में *तथ्यात्मक प्रस्ताव* के रूप में अपनी राय पर आए। उपरोक्त के अनुरूप, आचरण, एक बोधगम्य बाहरी तथ्य होने के नाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में परिभाषित "प्रत्यक्ष साक्ष्य" द्वारा साबित किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि गवाहों को गवाही देनी चाहिए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या देखा या सुना है।

26.2. परिवार के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति के आचरण द्वारा व्यक्त की गई राय या किसी भी व्यक्ति के पास अन्यथा इस विषय पर ज्ञान का विशेष साधन है, एक प्रासंगिक तथ्य है। यह गवाही साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के तहत प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में बनी हुई है।

27. साक्ष्य अधिनियम हमें प्रासंगिक तथ्यों की धारणा और भेदभाव पर सिद्धांत सिखाता है। एक प्रासंगिक तथ्य के रूप में अनुमत धारणा स्वचालित रूप से साबित तथ्य के बराबर नहीं होती है जब तक कि वह भेदभाव की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाता, अर्थात्, गवाह की प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और क्षमता का तिहरा परीक्षण न हो। यह *पोटेम सुब्बारायुडु और अन्य बनाम कोथापल्ली गांगुलु नायडू और अन्य*[5], में *गोविंदा बनाम चंपा बट*[6], आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश का हवाला देते हुए कहा गया है कि:

"17. गवाहों के मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन के लिए कोई सीधा सिद्धांत नहीं हो सकता है। गवाह की विश्वसनीयता न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार है। गवाह की प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और क्षमता जैसे तीन कानूनी परीक्षणों को पास करने के बाद, गवाह की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए, न्यायालय को विभिन्न मापदंडों पर विचार करना होगा

---

[4] आई.एल.आर. (1942) 2 कैल. 299, 309

[5] 2000 एस.सी.सी. ऑनलाईन ए.पी. 296

[6] ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 354

ताकि दो महत्वपूर्ण मानदंडों के मापदंडों पर परीक्षण करके बिंदु पर मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन की जा सके, जैसे कि विभिन्न अन्य मापदंडों के बीच संभावनाएं और आसपास की परिस्थितियां है' यहां तक कि जब विरोधी द्वारा कोई खंडन नहीं किया जाता है, तो उस पक्ष में परीक्षण किए गए गवाहों की स्पष्ट गवाही जिस पर बोझ है, संभावनाओं और आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में इसका परीक्षण किए बिना निहित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

28. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम वादी द्वारा भरोसा किए गए मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन करते हैं।

28.1 मुख्य परीक्षा में, अभियोजन गवाह 2, मोहम्मद खयामुल्ला ने कहा कि वह खदीजाबी और वादी, सईदा आरिफा परवीन दोनों को जानता था कि उसकी माँ और खदीजाबी की माँ पहले चचेरे भाई थे, इस तरह वह दोनों वादी से संबंधित था।

28.2 वह मकदुमपुरा में खदीजाबी और वादी के साथ एक ही घर में किरायेदार के रूप में रहता था, और वादी को स्कूल ले जाता था, जिससे उसके ज्ञान की पुष्टि होती थी कि खदीजाबी उसकी मां थी। खदीजाबी, सर्वेक्षण संख्या-107 के मालिक के रूप, उसकी केवल एक बेटी, वादी थी, और उसे 05.12.1988 को प्यार और स्नेह से 10 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। यह मौखिक उपहार खदीजाबी के घर में वादी खदीजाबी, अब्दुल बासित सब, अब्दुल रहमान सब, मुस्ताक अहमद और अयूब अली की उपस्थिति में किया गया था। इस गवाह की विश्वसनीयता गंभीर परीक्षण के दायरे में आती है जब गवाह ने मुश्ताक अहमद को 05.12.1988 के मौखिक उपहार के गवाहों में से एक के रूप में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि खदीजाबी ने वादी को भूमि और सभी कृषि उपकरणों का कब्जा सौंप दिया था और जब उसने 05.01.1989 को उपहार ज्ञापन को निष्पादित किया था तो वह भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि खदीजाबी ने दस्तावेज़ पर अपने अंगूठे का निशान लगाया, जिस पर वादी और दो गवाहों, सैयद अब्दुल बासित और मोहम्मद अब्दुल रहमान ने भी हस्ताक्षर किए थे, हालांकि उन्होंने खुद इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि दो गवाह पर्याप्त थे।

28.3 जिरह में गवाह ने कहा कि उसकी मां खदीजाबी की मां की पहली चचेरी बहन है। उन्होंने नोट किया कि खदीजाबी ने प्यार और स्नेह से वादी को 10 एकड़ जमीन का मौखिक उपहार दिया और कब्जा सौंप दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह मौखिक उपहार के समय उपस्थित थे और खदीजाबी ने अपनी बेटी को खेती के लिए एक हल और दो गायें दीं, जो कब्जे के वितरण का प्रतीक था। उनका कहना

है कि उपहार में दी गई 10 एकड़ भूमि कुल भूमि के दक्षिणी किनारे पर स्थित थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खदीजाबी का राशन कार्ड देखा था, जिसमें वादी को उनकी बेटी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और उसी के संबंध में स्कूल के दस्तावेज भी देखे थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वादी के पिता और माता की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अब्दुल बासित और अब्दुल बास का नाम एक ही था।

28.4 मौखिक साक्ष्य मुख्य रूप से इन परिस्थितियों में गवाही देने के लिए गवाह की क्षमता और विश्वसनीयता स्थापित किए बिना, रिश्ते आदि पर बोलने के लिए आगे बढ़ता है। ज्ञान के विशेष साधनों का अनुमान लगाने के लिए, गवाह अपने मौखिक साक्ष्य को छोड़कर किसी भी दस्तावेज का उल्लेख नहीं करता है। वादी द्वारा नहीं बताए गए पहलुओं से निपटने वाले मौखिक साक्ष्य दलीलों में हैं।

28.5 मुख्य परीक्षा में, अभियोजन गवाह 3 ने कहा कि वह वादी को जानता है और वह सैयद अब्दुल बासित की बेटी है, जिसे मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि वादी के पति, मुश्ताक अहमद, उनके भाई हैं। उन्होंने कहा कि शादी के प्रस्ताव से पहले, उन्होंने पूछताछ की थी और उन्हें पता था कि वादी सैयद अब्दुल बासित की बेटी थी। उन्होंने व्यक्तिगत ज्ञान से गवाही दी कि वादी अब्दुल बासित की बेटी है। गवाह ने आगे दावा किया कि वादी के पिता अब्दुल बासित की मृत्यु 09.09.2001 को हुई थी और उसे कभी भी अब्दुल बास के रूप में संदर्भित नहीं किया गया था।

28.6 अपनी जिरह में, वह मानता है कि वह वादी के पति का भाई है। उसने वादी और उसके रिश्तेदारों से वादी के माता-पिता के बारे में **पूछताछ** की थी। उन्होंने दावा किया कि अब्दुल बासित ने 1989 में उनकी बेटी को जमीन दी थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अब्दुल बासित और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं है और उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि उनकी एक बेटी है। यह पूछे जाने पर कि क्या उसने यह साबित करने के लिए वादी के दस्तावेज देखे थे कि वह अब्दुल बासित और खदीजाबी की बेटी है, तो उसने जवाब दिया कि वह यह जानता था क्योंकि वह एक रिश्तेदार था, और उसने इनकार किया कि वह उनका रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि मोहम्मद अब्दुल रहमान और एमए रहमानसाब के नाम अलग-अलग हैं, उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि वे एक ही व्यक्ति हैं। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसने वादी को अपना पूरा नाम और उम्र नहीं बताई

थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अब्दुल बासित को अब्दुल बास के नाम से भी जाना जाता है।

29 निचली अदालत डोलगोबिंद परिचा (उपर्युक्त) *और* चंदू लाल अग्रवाल (उपर्युक्त) *में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार गवाहों* अभियोजन *गवाह 2 और* अभियोजन *गवाह 3 के मौखिक साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा*। यह गवाहों की राय की विश्वसनीयता का स्वतंत्र रूप से आकलन करने और खदीजाबी और अब्दुल बासित के साथ वादी के संबंधों के बारे में अपना निष्कर्ष निकालने में विफल रहा। निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह 2 और अभियोजन पक्ष के गवाह 3 की गवाही की परीक्षण करते हुए, सही ढंग से पहचाना कि वादी के रिश्ते पर उनकी राय साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के तहत स्वीकार्य थी क्योंकि वे मृतक खदीजाबी के साथ वादी के संबंधों के बारे में ज्ञान के विशेष साधन वाले लोग थे। हालांकि, सबूत प्रथम दृष्टया धारा 50 के त्रिगुण परिक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं, और इस बात की मूल्यांकन नहीं करते हैं कि भले ही सबूत तीन आवश्यकताओं के अनुरूप हों, अब तक के सबूत एक मध्यवर्ती चरण में हैं। निचली अदालत ने प्रतिवादियों के सुझाव का उल्लेख किया और कहा कि गवाहों ने ज्ञान के विशेष साधनों का दावा किया। आगे की खोज यह है कि यह पर्याप्त होगा यदि उसके (गवाह) पास ज्ञान के विशेष साधन हैं, इसलिए सदस्यों के आचरण को देखने वाले व्यक्ति को ज्ञान के विशेष साधन के रूप में माना जाना चाहिए। इस मुद्दे का उत्तर पूर्व अभियोजन -8 और पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-8 में हस्ताक्षरों को देखकर दिया जाता है।

30 निचली अदालत के दृष्टिकोण में एक और अवैधता की मूल्यांकन करने के लिए, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत अदालतों की विवेकाधीन शक्ति पर ध्यान देते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 एक अदालत को विवादित हस्ताक्षरों, लेखन या मुहरों की तुलना दूसरों के साथ करने का अधिकार देती है जिन्हें स्वीकार किया गया है या प्रामाणिक साबित किया गया है। यह अदालत को अदालत में मौजूद किसी भी व्यक्ति को तुलना के उद्देश्य से कोई भी शब्द या आंकड़े लिखने का निर्देश देने की शक्ति भी देता है।

30.1 स्वीकृत या सिद्ध दस्तावेजों के साथ तुलना: धारा 73 का प्राथमिक कार्य अदालत को एक विवादित हस्ताक्षर या लिखावट की तुलना एक मानक दस्तावेज़ से करने की अनुमति देना है जिसे या तो पार्टियों द्वारा स्वीकार किया गया है या अदालत की संतुष्टि के लिए वास्तविक साबित हुआ है। तुलना अदालत द्वारा ही की जा सकती है। *फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य,*[7] में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक अदालत को लिखावट विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।

---

[7] 1966 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 55

न्यायालय ने माना कि जबकि अदालत धारा 73 के तहत एक विवादित हस्ताक्षर की तुलना एक स्वीकृत हस्ताक्षर से कर सकती है, किसी विशेषज्ञ की सहायता के बिना पूरी तरह से इस तुलना पर भरोसा करना खतरनाक होगा। न्यायालय ने पुष्टि के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अदालत की अपनी तुलना का उपयोग किसी विशेषज्ञ गवाह की गवाही का समर्थन करने के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में या इसके विपरीत किया जा सकता है, ।

30.2 न्यायालय द्वारा विवेकपूर्ण उपाय में तुलना: धारा 73 न्यायालय को दस्तावेजों की तुलना करने की शक्ति देती है। दस्तावेजों की तुलना करने की शक्ति और उपलब्ध शक्ति का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, और गंभीर मामलों में निर्णय के लिए अदालत का निष्कर्ष एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। निचली अदालत के फैसले से निम्नलिखित निष्कर्ष का अंश देना उचित है:

"21. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि, सैयद अब्दुल बासिथ पुत्र सैयद हुसैन साहेब के हस्ताक्षर के मामले में पूर्व अभियोजन*8 जो उपहार का ज्ञापन है, की तुलना अब्दुल बासिथ पुत्र सैयद हुसैनसाब के हस्ताक्षर* पूर्वप्रतिवाद*3 से* पूर्वप्रतिवाद*7 और* पूर्वप्रतिवाद*8 के हस्ताक्षर से की जाती है, कोई भी कह सकता है कि ये हस्ताक्षर एक हैं और वही केवल एक व्यक्ति के हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, अदालत दस्तावेजों में व्यक्ति के हस्ताक्षर की तुलना कर सकती है। हालांकि वादी ने दलील दी है कि सैयद अब्दुल बासित और अब्दुल बास पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कि सैयद अब्दुल बासिथ और अब्दुल बास नाम के दो व्यक्ति हैं, जो पूरी तरह से अलग हैं, कुछ भी* अभिलेख *पर नहीं रखा गया है।*

22. यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, पूर्व अभियोजन *8 और* पूर्व प्रतिवाद*3 से* पूर्व प्रतिवाद*8 में अब्दुल बासित या अब्दुल बास के पिता का नाम सैयद हुसैनसब के रूप में दिखाया गया है। यदि कुसनूर गांव में प्रदर्शन करने के लिए सामग्री है तो सैयद हुसैन साहब नाम के दो व्यक्ति थे और उनमें से प्रत्येक को सैयद अब्दुल बासित और अब्दुल बास नाम के बेटे मिले, तो वादी का यह कथन स्वीकार्य हो सकता है कि सैयद अब्दुल बासित और अब्दुल बास दोनों पूरी तरह से अलग हैं।* अभिलेख *पर इस तरह की सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए,* पूर्वअभियोजन *8 में सैयद अब्दुल बासित पुत्र सैयद हुसैनसाब के हस्ताक्षर की तुलना* पूर्वप्रतिवाद*3 से* पूर्वप्रतिवाद*8 में अब्दुल बास पुत्र सैयद हुसैन साहेब के हस्ताक्षर के साथ की जाती है, तो कोई आसानी से कह सकता है कि सैयद अब्दुल बासित को अब्दुल बास के रूप में भी बुलाया जाता था।*

23. जैसा कि वादी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है और पूर्वअभियोजन *8 में इसका उल्लेख किया गया है, सैयद अब्दुल बासित ने उपहार का ज्ञापन के गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर*

किए थे, कहा कि सैयद अब्दुल बासित के हस्ताक्षर पूर्वप्रतिवाद*3 से* पूर्वप्रतिवाद*8 में अब्दुल बास के हस्ताक्षर के साथ मेल खाते हैं, यह माना जा सकता है कि ये सैयद अब्दुल बासित और अब्दुल बास एक ही व्यक्ति हैं।*

24. पूर्व अभियोजन *8 पर सैयद अब्दुल बासित के हस्ताक्षर को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि वादी खदीजाबी और सैयद अब्दुल बासित की बेटी है। (...)"*

31.उपरोक्त विचार यह स्थापित करता है कि निचली अदालत एक दस्तावेज के आधार पर संबंध को स्वीकार करता है जिसे वादी द्वारा चुनौती दी जाती है, और हस्ताक्षर की तुलना प्रतिवादियों द्वारा विवादित दस्तावेज से की जाती है। अधिक विशेष रूप से, वादी ने स्पष्ट रूप से पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-5 के निष्पादन से इनकार कर दिया, जैसा कि अब्दुल बासित द्वारा किया गया था।

31.1 यह रिश्ते पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले सभी सबूतों के प्रकाश में मध्यवर्ती राय का मूल्यांकन करने के महत्वपूर्ण दूसरे चरण पर आगे नहीं बढ़ा। निचली अदालत ने गवाहों की राय को तौलने के लिए सबूत के एक टुकड़े के बजाय एक तथ्य के रूप में माना। इसने उनके दावे को रिश्ते के प्रमाण के रूप में लिया, एक निर्णायक राय बनाने के अपने कर्तव्य को दरकिनार करते हुए। इसने अभियोजन गवाह 2 और अभियोजन गवाह 3 के पूर्वाग्रह की संभावना को ध्यान में नहीं रखा, जो दोनों वादी के करीबी रिश्तेदार हैं। आचरण एक मध्यवर्ती कदम है, जो अदालत को एक राय का अनुमान लगाने की अनुमति देता है, लेकिन यह रिश्ते के अंतिम प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है। निचली अदालत द्वारा की गई चूक साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 और 60 के तहत आवश्यक साक्ष्य कठोरता को कमजोर करती है।

31.2 दोनों अदालतों ने मौखिक साक्ष्यों की अनदेखी की है कि वादी ने उर्दू माध्यम में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने की बात स्वीकार की है। कोई दस्तावेजी साक्ष्य दायर नहीं किया गया है, और वादी के दावे के कुल संदर्भ में प्रासंगिक दस्तावेजों को दाखिल न करने की मूल्यांकन की जाती है। अभियोजन पक्ष के गवाह 2 का कहना है कि उसने खदीजाबी के राशन कार्ड को देखा है जिसमें वादी को उसकी बेटी के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने इस संबंध में स्कूल के दस्तावेज भी देखे हैं। अभियोजनके गवाह 4 विवादित संपत्तिके भूमि मालिक के अगले पड़ोसी होने का दावा करता है। उसका साक्ष्य ज्यादातर वाद संपत्ति के वादी के कब्जे को साबित करने के लिए है। मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन को सीमित सूत्र में चित्रित नहीं किया जा सकता है। अदालत का अनुभव और विशेषज्ञता मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन करने में सक्षम

होगी। इस प्रक्रिया में, गवाह की विश्वसनीयता अदालत के लिए सर्वोपरि विचार है। वृतांत के क्रम में, कम से कम यदि एक तथ्य को विपरीत पक्ष द्वारा साबित या स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे प्रमाण या स्वीकारोक्ति से, अनुक्रमिक तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। आक्षेपित निर्णयों ने परिपत्र तर्क का सहारा लिया है, जो अस्वीकार्य और अवैध है।

32.हमने मौखिक साक्ष्यों और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया है। संक्षेप में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निचली अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 का उल्लेख किया है, और गवाहों की विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और क्षमता का परीक्षण किए बिना, एक अमूर्त तरीके से, माना है कि वादी खदीजाबी की बेटी है। निचली अदालत ने आगे पाया कि इन गवाहों को मात्र सुझाव गवाह 2 और 3 के साक्ष्य को बदनाम नहीं करता है। निचली अदालत यह नोट करने में विफल रहा कि वादी और गवाह, अपने साक्ष्य के आधार पर, अपने कब्जे में दस्तावेजों, अर्थात् स्कूल छोड़ने के अभिलेख , राशन कार्ड आदि को रोक रहे हैं। प्रशंसा में विकृति सभी भौतिक पहलुओं पर अभियोजन पक्ष के गवाह 1 से 3 के साक्ष्य में सुधार से स्पष्ट है।

33.उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए, हम देखते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह 2 और 3 के साक्ष्य को गवाहों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनके पास खदीजाबी के साथ वादी के ज्ञान का विशेष साधन है। हमारा मानना है कि मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन करने में मानक परीक्षणों का पालन करने में विफल रहे हैं, और वादी की स्थिति पर अमूर्त निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। साक्ष्य में स्वीकार्य प्रासंगिक तथ्यों पर जोर दिया गया है। यह मानते हुए कि साक्ष्य स्वीकार्य है, इसे त्रिगुण परिक्षण के अनुरूप होना चाहिए। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि स्थिति या संबंध का प्रमाण हमेशा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से होना आवश्यक नहीं है, लेकिन, जब मौखिक साक्ष्य वह आधार है जिस पर न्यायालय द्वारा राय बनाने की आवश्यकता होती है, तो न्यायालयों को किसी रिश्ते के बारे में आचरण पर एक राय को केवल एक प्रासंगिक तथ्य के रूप में मानने की अनुमति है। इसे '*तथ्यात्मक प्रस्ताव*' के रूप में भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वादी द्वारा खदीजाबी की बेटी के रूप में दावा किए गए दर्जे को स्वीकार करने के अपने दृष्टिकोण में आक्षेपित निर्णय उदार हैं। इस बात का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

बिंदु IV

34. वादी, घोषणा की राहत के लिए, दो आख्यान स्थापित करता है; अर्थात्, (क) कि 05.12.1988 को, खदीजाबी ने एक मौखिक उपहार/हिबा के माध्यम से, वादी को वाद संपत्ति में 10 एकड़ जमीन उपहार में दी। 05.01.1989 को, पूर्व-अभियोजन 8, उपहार विलेख का एक ज्ञापन, जिसमें पिछले मौखिक उपहार को दर्ज किया गया था, निष्पादित किया गया था, और (ख) 09.09.2001 मे अब्दुल बासित की मृत्यु हो गई, और वह खदीजाबी की संपत्ति की एकमात्र वारिस और उत्तराधिकारी बनी रही। अभियोजन पक्ष के गवाह 1 के रूप में, वादी ने गवाही दी कि एक वैध हिबा/मौखिक उपहार के तीन तत्वों का अनुपालन किया गया था, और 10 एकड़ की क्षेत्र वाली संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। वादी, प्राप्तकर्ता होने के नाते, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की मूल्यांकन करने के बाद उसके साक्ष्य की मूल्यांकन की जाती है। प्रतिवादियों ने मौखिक उपहार से इनकार कर दिया है और पूर्व अभियोजन-8, उपहार विलेख का एक ज्ञापन भी है। जैसा कि चर्चा की गई है, निचली अदालत ने मौखिक उपहार पर अविश्वास किया और पूर्व अभियोजन -8 भी। उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा नहीं बताए गए मामले को पेश करते हुए, हिबा को स्वीकार कर लिया।

35. अब्दुल रहीम बनाम एसके अब्दुल जबर[8]*,* रशीदा खातून बनाम आशिक अली[9] *,* हफीजा बीबी बनाम एसके फरीद[10] *,* और मंसूर साहेब बनाम सलीमा[11] *में*, इस न्यायालय ने हिबा के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण के अंतर्निहित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। हिबा जीवित व्यक्तियों के बीच एक स्वभाव है और मूल रूप से परोपकार का कार्य है। धार्मिक आधार पैगंबर मोहम्मद (उन पर शांति हो) से वापस आते हैं, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था, "आपस में उपहारों का आदान-प्रदान करें ताकि प्यार बढ़ सके।[12]

36.मौखिक उपहार और वैध मौखिक उपहार के प्रभाव को इस प्रकार दोहराया गया है:

36.1 मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले, दाता की ओर से देने की इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति। दूसरा, प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति, जो या तो निहित या स्पष्ट हो सकती है।

---

[8] (2009) 6 एस.सी.सी. 160

[9] (2014) 10 एस.सी.सी. 459

[10] (2011) 5 एस.सी.सी. 654

[11] (2023) एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 3809

[12] अल-मरघिनानी, बुरहान अल-दीन, अल-हियादाया, कुरान महल, कराची खंड III, पृष्ठ 283; मुल्ला, मुसलमान कानून के सिद्धांत, 20वां संस्करण, अध्याय XI (उपहार)

तीसरा, प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की विषय-वस्तु को वास्तव में या रचनात्मक रूप से अपने कब्जे में लेना।

36.2 मुस्लिम कानून के तहत एक उपहार को वैध होने के लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। एक मौखिक उपहार जो तीन आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है वह पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। केवल तथ्य यह है कि एक उपहार लेखन तक सीमित हो जाता है, उसके स्वभाव या चरित्र को नहीं बदलता है। उपहार को अभिलेख करने वाला एक लिखित दस्तावेज उपहार का औपचारिक साधन नहीं बन जाता है।

36.3 यह अंतर कि उपहार के लिखित विलेख को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है यदि यह "पूर्व उपहार के तथ्य का पाठ करता है" लेकिन पंजीकृत होना चाहिए यदि "लेखन उपहार के निर्माण के साथ समकालीन है" को "अनुचित माना जाता है और यह मुस्लिम कानून में उपहारों के नियम के अनुरूप नहीं है[13]।संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 ('संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम') की धारा 129 में मुस्लिम कानून के नियम को धारा 123 के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके लिए अचल संपत्ति के उपहार के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

36.4 वैध उपहार के लिए कब्जे की प्रतिपादन एक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। यह वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है। रचनात्मक कब्जे को दाता द्वारा प्रत्यक्ष कृत्यों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जो नियंत्रण को स्थानांतरित करने का स्पष्ट इरादा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, दाता राजस्व अभिलेख में प्राप्तकर्ता के नाम के उत्परिवर्तन के लिए आवेदन करता है।

36.5 कब्जे के वितरण को साबित करने के लिए मौखिक उपहार के तहत कार्य करने का निरंतर साक्ष्य महत्वपूर्ण है। प्राप्तकर्ता को इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर "विशेष नियंत्रण" प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि किराया एकत्र करके, या दाता द्वारा प्राप्तकर्ता की ओर से उत्परिवर्तन जैसे कार्य करना। इसके विपरीत, दाता के किराए का निरंतर संग्रह और प्राप्तकर्ता के स्वामित्व दस्तावेजो या उत्परिवर्तन अभिलेख पर नियंत्रण की कमी इस बात का प्रमाण हो सकती है कि कब्जा हस्तांतरित नहीं किया गया था।

---

[13] देखिए, हफ़ीज़ा बीबी (उपर्युक्त)

37. *मुसामुत कमरुन्निसा बीबी बनाम मुसामुत हुसैनी बीबी,* [14] में परामार्शदात्री परिषद ने माना कि कब्जे के हस्तांतरण का प्रमाण, विशेष रूप से विचार के अभाव में, मौखिक उपहार को सक्षम करने के लिए आवश्यक है। यह भी माना गया कि "न्यायालय कथित दाता की मृत्यु के बाद स्थापित मौखिक उपहार के मामले को सबसे अधिक सावधानी से, शायद संदेह के साथ भी, देखने के लिए बाध्य है; और अगर मामला केवल मौखिक गवाही पर टिका होता, तो शायद उनके आधिपत्य के सामने यह अपील नहीं होती। मौखिक उपहार के मामले को बाद की कार्रवाइयों से मजबूत किया गया जैसे कि उपहार को प्रचारित करना और सरकारी अभिलेख में नामों के दाखिल खारिज को लागू करने के लिए *मुख्तारनामा* (अधिकार पत्र) पर हस्ताक्षर करना। परामार्शदात्री परिषद ने मौखिक उपहार दिए जाने के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा की गई कई कार्रवाइयों पर विचार किया, जिसमें सरकारी भुगतान के लिए रसीदें दाखिल करना, आयकर का भुगतान करना और मौखिक उपहार के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए एक किरायेदार पर निष्कासन के लिए मुकदमा करना शामिल है।

38. मौखिक उपहार 24 एकड़ 28 गुंटा की कुल क्षेत्र में से 10 एकड़ तक सीमित है। मौखिक उपहार 05.12.1988 को बताया गया है, और कहा गया था कि पूर्व अभियोजन -8 को 05.01.1989 को निष्पादित किया गया था। पहली परिस्थिति, जो वादी द्वारा अस्पष्ट है, वह यह है कि खदीजाबी ने स्वयं संपूर्ण विवादित संपत्ति, यानी 24 एकड़ और 28 गुंटा के लिए अपने नाम के दाखिल खारिज का अनुरोध किया था। वादी की ओर से चिह्नित पूर्व अभियोजन -2, हाजी मोहम्मद यूसुफ से खदीजाबी में अधिकारों का अभिलेख के अदालती निर्णय और दाखिल खारिज को संदर्भित करता है। मौखिक उपहार, जैसा कि वादी द्वारा कहा गया था, समय के साथ पूर्वकाल था, और यदि यह वैध है, तो दाता 10 एकड़ की क्षेत्र तक मालिक नहीं रह गया। दाता और प्राप्तकर्ता की संभावना या आचरण कथित मौखिक उपहार के अनुरूप होगा कि वादी के नाम को 10 एकड़ की क्षेत्र तक उत्परिवर्तित किया जाना था। खदीजाबी के पक्ष में वाद संपत्ति की पूरी सीमा तक अधिकार, स्वामित्व और कब्जे का उत्परिवर्तन मौखिक उपहार पर गंभीर संदेह पैदा करेगा। दूसरी परिस्थिति यह है कि खदीजाबी की मृत्यु 29.11.1990 को हुई थी और स्वर्गीय खदीजाबी के पति अब्दुल बासित ने मुकदमे की अनुसूची की कुल क्षेत्रों के लिए उनका नाम दर्ज करवाया था। यदि वाद संपत्ति का दावा करने के लिए उसके द्वारा बताए गए दोहरे कथन स्थापित हो जाते हैं, तो वादी, दान प्राप्त और उत्तराधिकारी दोनों के रूप में, उसके पक्ष में दाखिल खारिज मिला होगा, लेकिन अब्दुल बासित के पक्ष में नहीं। प्रतिवादी, पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 के माध्यम से, दावा करते हैं कि उन्होंने अब्दुल बास (अब्दुल बासित) से विवादित संपत्तिखरीदी है। जैसा कि पूर्व प्रतिवाद-9 से प्रतिवाद-43 द्वारा प्रमाणित किया गया है, प्रतिवादियों के

---

[14] 1880 यू.के.पी.सी. 36

नाम अधिकारों का अभिलेख में दर्ज किए गए हैं। अब्दुल बासित की मृत्यु 09-09-2001 को हुई थी। वादी, या तो दान करने वाली के रूप में अपनी क्षमता में, या कम से कम अब विवादित संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में, अधिकारों का अभिलेख में अपना नाम दर्ज करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। यह स्वयंसिद्ध है कि हिबा तत्काल प्रभाव से संचालित होता है और हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति पर उसके नियंत्रण और स्वामित्व से वंचित करता है।[15] परामार्शदात्री परिषद ने हिबा के माध्यम से हस्तांतरण को उचित मान्यता देते हुए निर्धारित किया कि कब्जे का सबूत एक महत्वपूर्ण विचार है। *रशीदा खातून (उपर्युक्त)* मौजूदा मुद्दे की परिस्थितियों के करीब एक मामला है।

38.1 रशीदा खातून *में,* किराया वसूलने की वादी की याचिका स्वीकार नहीं की गई क्योंकि कोई किराए की रसीद दाखिल नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि कथित उपहार के बाद दाता ने किराए की रसीदें जारी करना जारी रखा, जिसे प्राप्तकर्ता के कब्जे के दावे के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बात के सबूत का अभाव कि भूमि उत्परिवर्तित थी राजस्व अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ता के पक्ष में प्राप्तकर्ता के कब्जे के दावे के खिलाफ एक बिंदु माना जाता था। प्राप्तकर्ता का मालिकाना हक विलेख नहीं होना अदालत द्वारा विचार किया गया एक अन्य कारक था। इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वादी वास्तविक या रचनात्मक कब्जे को साबित नहीं कर सकता है, जिससे मौखिक उपहार अधूरा हो जाता है।

38.2 इसलिए, उपहार के तहत कार्य करने का साक्ष्य (उदाहरण के लिए, किराया एकत्र करना, स्वामित्व धारण करना, उत्परिवर्तन) कब्जे के दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है। जबकि मुस्लिम कानून एक लिखित दस्तावेज के बिना मौखिक रूप से उपहार देने की अनुमति देता है, इस तरह के उपहार की वैधता सभी तीन आवश्यक तत्वों, विशेष रूप से कब्जे के वितरण के प्रदर्शन पर निर्भर है। अदालतें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कब्जा वास्तव में स्थानांतरित किया गया था, यह निर्धारित करने के लिए प्राप्तकर्ता के कार्यों और संपत्ति पर नियंत्रण के "समकालीन" और "निरंतर" सबूतों की परीक्षण करेंगी। सबूतों की कमी (उदाहरण के लिए, किराया इकट्ठा करने में विफलता, दाता का निरंतर नियंत्रण, उत्परिवर्तन की कमी) यह साबित करने की ओर ले जाएगी कि किसी भी लिखित घोषणा की परवाह किए बिना उपहार कभी पूरा नहीं हुआ था।

39. मिसालें यह हैं कि एक मौखिक उपहार के माध्यम से एक वैध हस्तांतरण का गठन करने के लिए, दाता द्वारा घोषणा की तीन समकालीन शर्तें, प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति, प्राप्तकर्ता

---

[15] रशीदा खातून (उपर्युक्त)

द्वारा कब्जा और समकालीन साक्ष्य के माध्यम से कब्जे को स्थापित करना जारी रखना ताकि यह दिखाया जा सके कि हिबा पर कार्रवाई की गई है। हिबा का उपयोग एक आश्चर्यजनक साधन के रूप में नहीं किया जाता है और किसी पक्ष की सुविधा के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण में अंकुरित नहीं हो सकता है। इसके अलावा, हिबा की पवित्रता के अनुरूप बनाए रखने के लिए, यह दाता, दाता और विषय वस्तु में रुचि रखने वाले तीसरे व्यक्ति के हित में है कि हिबा को गोपनीयता के बजाय सार्वजनिक ज्ञान में सभी तीन आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करके कार्य किया जाता है। न्यायालय मौखिक उपहार के माध्यम से हस्तांतरण को मान्यता देते हुए साक्ष्य के माध्यम से समकालीन आवश्यकताओं और कब्जे की पूर्ति की मूल्यांकन करते हैं। वैध मौखिक उपहार का गठन करने के लिए कब्ज़ा महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। अदालतें दलील और साबित की गई परिस्थितियों से एक पक्ष के कब्जे को मानती हैं। मौजूदा मामले में, एक सुसंगत राजस्व अभिलेख है, पूर्व अभियोजन -2, पूर्व अभियोजन -3, पूर्व अभियोजन -4, पूर्व अभियोजन -5 और पूर्व प्रतिवाद-9 से प्रतिवाद-43 राजस्व अभिलेख में दिखाया गया है कि प्रतिवादियों के नाम अधिकारों का अभिलेख में दर्ज किए गए हैं और उनके पूर्ववर्तियों को ब्याज में रखा गया है, स्वामित्व और कब्जे दोनों पंक्ति में वादी मौखिक साक्ष्य रखता है, और ऊपर अभिव्यक्त परिस्थितियाँ यह स्वीकार करने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करती हैं कि एक वैध मौखिक रहा है

किसी भी क्षमता में उपहार, अर्थात, एक बेटी के रूप में या अन्यथा, वादी के पक्ष में आक्षेपित निर्णय वादी के पक्ष में *तदवचनतः* बयानों पर कब्जा मानते हैं, और नीचे की अदालतों ने वर्षों के लंबे अंतराल की मूल्यांकन नहीं करने और वाद संपत्ति के संबंध में वादी की चुप्पी जारी रखने में गंभीर त्रुटि की। अगला अंग यह है कि क्या पूर्व अभियोजन -8 पिछले लेनदेन को अभिलेख करने वाले एक ज्ञापन के रूप में संतुष्ट करता है और वादी की सहायता के लिए आएगा, कम से कम 10 एकड़ की सीमा तक, जो कि दिया गया है। पूर्व अभियोजन -8 में खदीजाबी का दीर्घकालिक प्रोत्साहन है। मूल वाद संख्या 68/1971 में वादपत्र को प्रतिवाद -44 के रूप में चिह्नित किया गया है। खदीजाबी ने उर्दू में वादपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, और जिरह के दौरान, अभियोजन पक्ष के गवाह 2 ने विशेष रूप से कहा कि खदीजाबी हस्ताक्षर कर रही थी, न कि उसे एल टी आई चिपका रही थी। यह असंगति अस्पष्टीकृत रही। इसके अलावा, पूर्व अभियोजन -8 के तहत, खंड 5 में, जिसमें लिखा है कि प्राप्तकर्ता इसके बाद दानकर्ता से किसी भी हस्तक्षेप, दावे या मांग के बिना शांतिपूर्ण ढंग से भूमि संपत्ति को धारण करेगा और उसके सभी समावेशन के साथ उसका आनंद लेगा। पूर्व अभियोजन -8 05.12.1988 को किए गए कब्जे और हस्तांतरण को झुठलाता है। उपरोक्त से, वादी के इच्छुक गवाहों से स्व-सेवारत और मौखिक साक्ष्य को छोड़कर, वादी को दिए

जाने के कब्जे पर कोई सबूत नहीं है, चाहे वह वास्तविक हो या रचनात्मक। दूसरी ओर, वादी द्वारा जिन प्रदर्शनों पर भरोसा किया गया है, प्रतिवाद -8 से प्रतिवाद -43 के साथ मिलकर, यह मानते हुए सक्षम नहीं होते हैं कि वादी के पास विवादित अनुसूची के 10 एकड़ जमीन पर कब्जा बना हुआ है। उच्च न्यायालय मामूली बदलावों, यदि कोई हो, को समझाने में उदार था। पूर्व अभियोजन -8 वादी के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। सम्मान के साथ, हम उक्त दृष्टिकोण की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं। नतीजतन, हिबा और पूर्व अभियोजन -8 के तहत वादी का दावा, कब्जे पर सबूत के अभाव में, विफल हो जाता है, और इस बिंदु का उत्तर प्रतिवादियों के पक्ष में दिया जाता है।

बिंदु V

40.अतिरिक्त मुद्दा संख्या 1 यह है कि क्या वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है। निचली अदालत ने इस मुद्दे का नकारात्मक और वादी के पक्ष में जवाब दिया। निचली अदालत का तर्क है कि कार्रवाई का कारण 14.10.2013 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादियों ने कथित तौर पर वादी को मुकदमे की संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की; और इस प्रकार, संक्षिप्त विवरण करता है कि उक्त तिथि पर वाद संपत्ति में वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप है।

41.28.10.2013 को, वर्तमान मुकदमा मूल वाद संख्या 212/2013 यह घोषणा के लिए दायर किया गया था कि वादी विवादित संपत्तिका मालिक और मालिक है, और यह घोषणा करता है कि प्रतिवादियों के पक्ष में 25.02.1995 के बिक्री विलेख, पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7, अमान्य है। अनुच्छेद 9 और 10 में वादपत्र कार्रवाई का कारण बनाने वाली परिस्थितियों को संदर्भित करता है। संक्षिप्तता के लिए, हम ध्यान दें कि क्या कार्रवाई का कोई कारण है या क्या मुकदमा परिसीमा की अवधि के भीतर है, जो वादपत्र में कथनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, लिखित बयान में दिए गए कथन इस पहलू में निर्धारक नहीं हैं।

42. परिसीमा अधिनियम, 1963 ('परिसीमा अधिनियम') का अनुच्छेद 58 घोषणात्मक वाद में परिसीमा की अवधि का प्रावधान करता है। "जब मुकदमा करने का अधिकार पहले अर्जित होता है" शब्दों का उपयोग, जैसा कि अनुच्छेद 58 में उल्लेख किया गया है, बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि तीन साल की सीमा को उस तारीख से गिना जाना चाहिए जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार अर्जित होता है।[16] स्वामित्व के लिए घोषणात्मक राहत वादी के मौखिक उपहार और उत्तराधिकार पर आधारित

---

[16] निखिला दिव्यांग मेहता एवं अन्य बनाम हितेश पी. सांघवी एवं अन्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 485

है। वादी पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 को अलग करने के लिए भी प्रार्थना करता है, जिसके लिए परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 लागू होता है। विचार का सार यह है कि क्या वादपत्र में दिए गए कथन कार्रवाई के कारण को जीवित रखते हैं, या वादी की ओर से रचनात्मक सूचना और लापरवाही से, भले ही, एक निश्चित समय पर, कार्रवाई का कोई कारण था, चाहे वह समय के अनुसार वर्जित हो या नहीं, यह मामले की जड़ है।

43.इस मामले में समयसीमा का उल्लेख करना प्रासंगिक हो जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कार्रवाई का कारण जारी है, या, वादी की ओर से रचनात्मक सूचना और लापरवाही से, कार्रवाई का कारण समय के साथ वर्जित है। वादी द्वारा दो दावे किए गए हैं: पहला, 10 एकड़ के मौखिक उपहार पर, और दूसरा, इस दावे पर कि वह मुकदमे की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी है।

43.1 मौखिक उपहार के संबंध में डोमिनोज़ (सिद्धांत) 05.12.1988 को गति में तय किया गया है, जब खदीजाबी ने कहा कि उन्होंने सर्वेक्षण संख्या 107 में 10 एकड़ जमीन मौखिक रूप से उपहार में दी थी। 05.01.1989 को, इस मौखिक उपहार को उपहार ज्ञापन के रूप में लिखा गया था। खदीजाबी की मृत्यु 29.11.1990 को हुई और अब्दुल बासित की मृत्यु 09.09.2001 को हुई। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने 1989, 1990, 2001 में या 2013 तक के अंतराल में दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं किया, स्वर्गीय खदीजाबी से विवादित संपत्ती के हस्तांतरणकर्ता के रूप में अपने अधिकार का दावा किया।

43.2 इस दावे के संबंध में कि प्रतिवादी वाद संपत्ति में 24 एकड़ और 28 गुंटा का कानूनी उत्तराधिकारी है, यह ध्यान रखना उचित है कि खदीजाबी की मृत्यु 29.11.1990 को हुई थी, और अब्दुल बासित ने 23.05.1991 मे पूर्व के माध्यम से अपने नाम पर 24 एकड़ और 36 गुंटा के लिए अपना नाम बदल दिया था। प्रतिवाद -2. इसके बाद, 25.02.1995 को, अब्दुल बासित द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में पांच बिक्री विलेख निष्पादित किए गए, और अधिकार अभिलेख में प्रतिवाद -9 से प्रतिवाद -23 प्रविष्टियां कब्जे की धारणा का संकेत देती हैं।

44.पूर्व अभियोजन -1 और अभियोजन -2 में दाखिल खारिज प्रविष्टि, पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 के निष्पादन के साथ मिलकर, वाद संपत्ति पर वादी के दावे के लिए संभावित शरारत के स्रोत हैं। वादी ने कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर अधिकार अभिलेख, या पंजीकृत बिक्री विलेखों के रखरखाव को चुनौती देने में समय पर कार्रवाई नहीं की है। 23 वर्षों की अवधि के लिए आचरण को एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के आचरण के रूप में मूल्यांकन

नहीं की जा सकती है, लेकिन यह उस देखभाल का उपयोग करने में विफलता के बराबर है जो एक उचित रूप से विवेकपूर्ण और सावधान व्यक्ति इन परिस्थितियों में उपयोग करेगा। कानून में लापरवाही कर्तव्य के पालन में विफलता का प्रतीक है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 में व्याख्या खंड रचनात्मक सूचना से संबंधित है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि विशिष्ट परिस्थितियों में एक उचित व्यक्ति द्वारा की जाने वाली परीक्षण नहीं की जाती है, तो अदालतें, रचनात्मक सूचना के माध्यम से, ऐसे व्यक्तियों पर ज्ञान आरोपित कर सकती हैं। इस प्रकार, न्यायसम्य में रचनात्मक सूचना एक ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है जिसे एक तथ्य को जानना चाहिए जैसे कि वह वास्तव में इसे जानता है।[17]

45.वर्तमान मामले में, वादी के पास 05.01.1989, 29.11.1990, 25.02.1995 और 09.09.2001 मे वाद संपत्ति को अपने नाम पर बदलने का अवसर था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने 2013 तक मुकदमा दायर नहीं किया, जो किसी भी मामले में, तीन साल की सीमा अवधि से अधिक है। इसलिए, हम वर्तमान मामले में रचनात्मक सूचना के माध्यम से ज्ञान को आरोपित करते हैं, और परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का एक निरंतर कारण था।

46.इसके अलावा, बिक्री के उपकरणों (पूर्व प्रतिवाद -3 से प्रतिवाद -7) को अलग करने के लिए, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत मुआयना को पूरा किया जाना चाहिए। यह स्वयंसिद्ध है कि एक अनुमान है कि एक पंजीकृत दस्तावेज़ वैध रूप से निष्पादित है। इसलिए, एक पंजीकृत दस्तावेज *प्रथम दृष्टया* कानून में मान्य होगा। इस प्रकार, सबूत की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जो अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत पेश करता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी उक्त अनुमान का खंडन करने में सक्षम नहीं है।[18] दिलचस्प बात यह है कि आक्षेपित निर्णय में, मौखिक उपहार या वाद संपत्ति के दावे का कोई सार्वजनिक अभिलेख नहीं होने के बावजूद प्रतिवादियों के खिलाफ रचनात्मक सूचना लगाया जाता है। परिस्थितियों को कालानुक्रमिक रूप से समझाया गया है, और मामले में वादी के लिए कार्रवाई का सबसे पहला कारण तब था जब पूर्व अभियोजन -2, दिनांक 06.06.1989, खदीजाबी के कहने पर अस्तित्व में लाया गया था, और कार्रवाई का कारण फिर से उत्पन्न हुआ है जब पूर्व अभियोजन -3 को अस्तित्व में लाया गया था, स्वर्गीय अब्दुल बासित द्वारा वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए। अब्दुल बासित के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 02.05.1995 को पूर्व प्रतिवाद-3 से प्रतिवाद-7 को निष्पादित किया था। प्रतिवाद के नाम नामांतरण कर दिए गए हैं, और निरंतर लापरवाही के परिणामस्वरूप पूर्व प्रतिवाद-3 से

---

[17] नूरुल होदा बनाम बीबी रईफुन्निसा, (1996) 7 एस.सी.सी. 767

[18] प्रेम सिंह एवं अन्य बनाम बिरबल एवं अन्य, 2006 ए.आई.आर. एस.सी. 3608

प्रतिवाद-7 द्वारा कवर किए गए लेनदेन की रचनात्मक सूचना दी जाएगी। आक्षेपित निर्णय इस बात का जवाब देने में रचनात्मक सूचना के प्रभाव की मूल्यांकन करने में विफल रहे कि मुकदमा सीमा की अवधि के भीतर है या नहीं। परिस्थितियों पर विचार करने और इस बिंदु पर मिसालों को लागू करने पर, हम मानते हैं कि 28.10.2013 को दायर किया गया मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है, विशेष रूप से मांगी गई राहत के लिए। इस बात का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

47. उपरोक्त कारणों और चर्चा के लिए, आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है; वादी का मुकदमा, मूल वाद संख्या 212/2013, खारिज कर दिया जाता है; और दीवानी अपील की अनुमति है। सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटान किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

† *शीर्ष टिप्पणीया* दिव्या पांडे के द्वारा *तैयार किए गए:*

यह अनुवाद (तलत परवीन) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया ।